

अनुगामिनी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पीपीपी मोड में किया जाएगा पुनर्विकास 3 पीएम को परीक्षा नहीं, पेपर लीक कर करनी चाहिए चर्चा 8

जब भी जरूरत पड़ेगी सीबीआई को बुलाया जाएगा : सीएम

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 01 अप्रैल। सिक्किम विधानसभा के बजट अधिवेशन का चौथे दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग के निधन पर शोक प्रस्ताव के साथ आरम्भ हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष एलबी दास ने अपने संदेश में स्वर्गीय बीबी गुरुंग के निधन पर शोक प्रकट करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने एक अधिभावक के तौर पर बीबी गुरुंग के साथ गुजारे अपने दिनों को याद किया। गौरतलब है कि बीबी गुरुंग का गत 28 मार्च को गंगटोक के लुम्से स्थित आवास पर निधन हो गया था। इसी बीच आज विधानसभा में प्रश्न काल हुआ और चार विधेयक भी पेश किये गये।

मई 2020 को आई अचानक बाढ़ में बे साइड के साथ ही थोलुंग ब्रिज का भी ढांचा ढह गया था। इसके कारण योजना में विलम्ब हुआ है। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दी गयी है और अब उनके जवाब का इंतजार है। वहीं उन्होंने कायुम ब्रिज का निर्माण कार्य जारी रहने की जानकारी भी दी।

साथ ही उत्तर सिक्किम के अपर जंगू में ब्रिज निर्माण कार्य के बारे में मंत्री ने बताया कि कनक नदी पर दो लेन के इस ब्रिज निर्माण हेतु कार्य में कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण देरी हुई है। इसका निर्माण कार्य गुरुगाम, हरियाणा के नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन को दिया गया है।

प्रायोजित योजनाओं में किया जायेगा।

कृषि मंत्री ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत उत्पादन प्रोत्साहन राशि की पहली तथा दूसरी किश्त के तौर पर किसानों को उनके बैंक खातों में दो करोड़ तीन लाख बेरासी हजार एक सौ सड़सठ रुपये दिये जा चुके हैं। वहीं उन्होंने शीघ्र ही और 61329413 रुपये का बैंक खातों में और भुगतान किये जाने की जानकारी भी दी।

वहीं एक पूरक प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में जैविक खेती के बढ़ावे हेतु विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। इस दिशा में उन्होंने सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी के गठन का जिक्र किया।

इसके बाद विधायक पिन्छो नामग्याल लेप्चा द्वारा पूछे गये सवाल पर राज्य के भू राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने बताया कि 27-28 जून, 2020 की बारिश के बाद हुए भूस्खलन में साक्चोंग-पेंटोंग जीपीयू के बे, पांसिंगडांग-साप्पो जीपीयू के पांसिंगडांग तथा शिपयेर जीपीयू प्रभावित हुए थे। उसके बाद वहां से प्रभावितों को सुरक्षित

भ्रष्टाचार रोधी इकाइयों को मिलेगी पूरी स्वतंत्रता



जगहों पर ले जाया गया तथा मुआवजे का भी वितरण किया गया। वहीं उन्होंने इस सम्बंध में रामोन तथा अपर शिप गांवों में हुए भूस्खलन का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान हेतु निवासियों के पुनर्वासन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को वित्त मंजूरी हेतु भेजी गयी योजना की भी जानकारी दी।

विधायक कर्मा सोनाम लेप्चा द्वारा राज्य में लम्बित भूमि मुआवजा विधेयक व भुगतान के सम्बंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में भू राजस्व मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण करने पर जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद उसे भूमि राजस्व विभाग को भेज दिया जाता है। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होती है।

इस दौरान विधायक डीआर थापा द्वारा राज्य सरकार द्वारा उठाये गये भ्रष्टाचार निरोधक कदमों के बारे में पूछे गये प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री गोले ने सदन को सूचित किया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इन्टेलिजेंसमेंट द्वारा भ्रष्टाचार मामलों की जांच के सम्बंध में सहमति पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने

विधानसभा में पवन चामलिंग ने प्रकट किया अपना अहंकार : सी.पी. शर्मा

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 01 अप्रैल। सिक्किम विधानसभा में बजट अधिवेशन के तीसरे दिन गुस्वार को राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री द्वारा पेश किये गये बजट अधिभाषण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री तथा एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिंग को टिप्पणी पर सत्ताधारी एसकेएम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।



पार्टी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बजट भाषणों का अध्ययन किये बगैर ही विधानसभा में उपस्थित होकर उन पर टिप्पणी करना पूर्व मुख्यमंत्री के अहंकार को ही दर्शाता है। एसकेएम के प्रवक्ता सीपी शर्मा ने इस सम्बंध में एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि सिक्किम तथा यहां की जनता के बेहतर भविष्य हेतु तैयार किये गये बजट को लेकर यदि वह असंतुष्ट हैं तो उन्हें सदन में उसे लेकर बहस करनी चाहिए थी।

भंग कर वे इसका दोष वर्तमान राज्य सरकार पर डाल रहे हैं। यह सभी को पता चल गया है। ऐसे में उनकी बातों पर बहस कर वर्तमान सरकार अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती है।

उन्होंने आरोप लगाया, सदन के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को सबूतों के साथ पेश करने पर पानी-पानी हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने उसे छिपाने के लिये ही सदन के बाहर जाकर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपनी भड़स निकाली है। उन्होंने कहा, हम सभी इस अपेक्षा में थे कि 38 वर्षों के लम्बे राजनीतिक जीवन में 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति की भद्रता, अनुशासन तथा बहस के तरीके से कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन विधानसभा में उपस्थित सभी लोगों ने उनके अंदर केवल अहंकार को ही देखा है।

प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व मुख्यमंत्री पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तथा जनता के समक्ष अपनी असलियत छिपाने हेतु अनावश्यक मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए उन्हें राजनीति को व्यापार समझने की मानसिकता त्यागने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं आगे कहा गया है कि एसकेएम द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की योजनाओं को विफल कर दिये जाने के कारण ही वे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

एसकेएम प्रवक्ता के अनुसार तीन वर्षों बाद विधानसभा में आकर बोलने न देने का आरोप लगाया, यह सदन में उनके भ्रष्टाचार साबित होने के बाद ह छटपटहट ही है। उन्होंने कहा, सदन में सभी को बोलने का मौका मिला है, ऐसे में उन्हें समय कैसे नहीं मिला ?

विज्ञप्ति में आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस समय विधानसभा में उनकी उपस्थिति जरूरी थी, उस समय वे वहां उपस्थित नहीं थे। जिस दिन विधानसभा में बजट पारित करना था, उसी दिन वह बजट पर सवाल उठा सकते थे। ऐसा करने की बजाय उन्होंने बाहर जाकर इस पर सवाल क्यों उठाये ? वहीं जनता यह पूछेगी कि उन्होंने बजट पर बहस करने की बजाय पार्टी कार्यालय जाने की जल्दी क्यों दिखायी ? यदि वह जनता की भलाई चाहते तो पार्टी के काम छोड़ कर बजट पर बहस कर सकते थे। एसकेएम उनके बेबुनियाद आरोपों का खंडन करते हुए स्वस्थ विचारों के साथ आने की सलाह देती है।

एसकेएम प्रवक्ता ने आगे कहा कि इतने वर्षों में पवन चामलिंग द्वारा सदन के शिष्टाचार, अनुशासन तथा मर्यादा को नहीं समझ सकना पूरे सिक्किम समाज के लिये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन चामलिंग द्वारा राज्य के युवाओं को पंगु बनाने की उनकी प्रयोगशालाएं अब बंद हो गई हैं। ऐसे में बाहरी आतंकियों की सहायता से राज्य की शांति-व्यवस्था

के साथ एक 32 इंच का टीवी भी दिया जा रहा है। साथ ही आगामी वर्षों में भी सरकार की ओर से ऐसे घरों का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि पूर्णहांग सुब्बा ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री पीएस गोले के नेतृत्व में मौजूदा सरकार इस योजना का कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगामी वर्षों में भी और गरीब आबाद को अच्छे घर बनाकर देने की जानकारी दी। इस अवसर पर (शेष पृष्ठ ०३ पर)

संदिग्ध युवाओं का एसडीएफ से कोई लेनादेना नहीं : विष्णु दुलाल

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 01 अप्रैल। एसडीएफ के प्रचार प्रसार मामले के सचिव विष्णु दुलाल ने कहा कि राजधानी के नामनाम स्थित एक होटल से पकड़े गए सात संदिग्ध युवाओं में से किसी का भी संबंध एसडीएफ से नहीं है।

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि एसपी तेंजिंग लोदोन लेख्चा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पकड़े गए युवाओं के संबंध एसडीएफ पार्टी से है। दुलाल ने कहा कि पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि पकड़े गए किसी भी युवा का पार्टी से कोई संबंध नहीं है और पार्टी के किसी भी पद पर नहीं हैं। पार्टी एपी के बयान का खंडन करती है।

घोषणापत्र में किए वादों को पूरा कर रही है सरकार : तामलिंग

गरीबों के लिए बनाए गए 60 आवासों का उद्घाटन

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 01 अप्रैल। मानेबुंग-देंताम क्षेत्र के देंताम खंड विकास कार्यालय के अधीन विभिन्न वाडों में सिक्किम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निर्मित 60 आवासों का आज विधिवत उद्घाटन कर उनकी चाबियां लाभान्वितों को सौंपी गयी। सिक्किम सरकार की योजना के अंतर्गत उक्त क्षेत्र के आठ पंचायतों के कुल 103 घर विहीन परिवारों में से 60 परिवारों के लिये आज ये घर दिये गये हैं।

डीआर बिष्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 10 परिवारों को पहले ही घर दिये जा चुके हैं। अब शेष 33 परिवारों के लिये भी घरों का निर्माण हो चुका है और उन्हें भी शीघ्र ही घर सौंप दिये जायेंगे। आज उक्त घरों के उद्घाटन अवसर पर मानेबुंग-देंताम क्षेत्र प्रभारी पूर्णहांग सुब्बा, आईपीआर सलाहकार बीरेन्द्र तामलिंग, अध्यक्ष जेबी तामलिंग, अध्यक्ष पेमा वांग्चु शेर्पा, देंताम महकमा अधिकारी एनके कार्की, अतिरिक्त जिला विकास सूरत गुरुंग, बीडीओ देंताम डीआर बिष्ट, क्षेत्रीय सभापति अनिता राई के अलावा अन्य विभागीय कर्मचारी एवं आमलोग उपस्थित थे।



इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में बीडीओ डीआर बिष्ट ने बताया कि उक्त पंचायत क्षेत्र में गरीबों के लिये आवास निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है और अभी

तक 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष बीरेन्द्र तामलिंग ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किये वादे के अनुसार राज्य में असहाय व गरीबों के लिये घर निर्माण कार्य सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने बताया, 17 लाख 51 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इन घरों के साथ लाभान्वितों को एक सोफा सेट, सेंटर टेबल, आलमारी, सिंगल बेड, डबल बेड

बीजेपी विधायक फर्वती तमांग ने की शारीरिक शिक्षा कॉलेज खोलने की मांग



अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 01 अप्रैल। सिक्किम विधानसभा में जारी बजट सत्र में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायक फर्वती तमांग ने राज्य सरकार को सिक्किम में शारीरिक शिक्षा कॉलेज खोलने का सुझाव दिया है। इस पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने निकट भविष्य में मल्ली में इस तरह की परियोजना लागू किये जाने

का आश्वासन दिया है। सिक्किम में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय न होने के कारण राज्य के विद्यार्थियों को बाहर जाकर उक्त विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बारे में बोलते हुए भाजपा विधायक तमांग ने कहा, मैं राज्य सरकार से सिक्किम में विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा हेतु एक कॉलेज खोलने का आग्रह करती (शेष पृष्ठ ०३ पर)

पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे में पर्यटक व पायलट की मौत

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 01 अप्रैल। तेलंगाना के एक 23 वर्षीय पर्यटक और पैराग्लाइडिंग पायलट की आज शुकुवार सुबह पायलट के नियंत्रण खो देने के बाद लाचुंग नदी में गिर कर बह जाने के बाद मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्व जिले के जिले के रेसिथांग के थामी दारा निवासी संदीप गुरुंग (26) और खम्मम, हैदराबाद, तेलंगाना की रहने वाली ईशा रेड्डी सांकेप्ली (23) के रूप में हुई है।



पुलिस ने कहा कि ईशा एक गुप के साथ लाचुंग पहुंची थी। जिलाधिकारी उत्तर एबी कार्की ने कहा कि छह घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद शव को बरामद कर लिया गया। लगभग 9:30 बजे पैराग्लाइडर संदीप और पर्यटक ईशा ने लाचुंग व्यू प्वाइंट से अपनी उड़ान भरी। वे गलती से लाचुंग के फाका

स्थानीय लोगों और सेना और आईटीबीपी कर्मियों द्वारा बचाव अभियान चलाया गया। कार्की ने कहा कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसटीएनएम अस्पताल भेज दिया गया है।

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ शामिल हुए राज्यपाल



अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 01 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता, मंत्रालय द्वारा ताल कटोरा स्टैडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भी आज राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिक्किम के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षा विभाग

के अधिकारी एवं शिक्षकों के संग इस कार्यक्रम को देखा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सम्पूर्ण भारत में दूरदर्शन पर किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों को प्रधानमंत्री के अनमोल वचनों को आत्मसात करने का आह्वान किया तथा साथ ही शिक्षा विभाग एवं स्कूलों को गायत्री मंत्र लिखित 'थान्का' भेंट किया। 'परीक्षा पे चर्चा' प्रधानमंत्री

का संवादात्मक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों में परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास जगाना है ताकि बच्चे परीक्षा के बोझ एवं भविष्य की चिंता के तले न दबें। तनाव रहित और हंसते-खेलते उत्सव के रूप में परीक्षा देना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है और इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जीवन की हर परीक्षा में मन जितना प्रसन्न होता है, नतीजा उतना ही अच्छा होता है।

अमेरिकी दवाब में नहीं झुकेगा भारत : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका से मिल रही चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत रूस से और भी कच्चा तेल खरीदेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मॉस्को से और तेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। रूस से तेल की खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जब हमें डिस्काउंट रेट पर तेल मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदें? उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र हित और उसकी जरूरतों को तर्जिह देती हूँ। हमने मॉस्को से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अगर हमें कच्चा तेल कम दाम पर ऑफर किया जाएगा तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे जिससे हमारे देश की जनता को फायदा हो।

गौरतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस पर अमेरिका कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका के डर से दुनिया के कई देश रूस से अपना व्यापार बंद कर चुके हैं। यही वजह है कि करीब चालीस दिनों से युद्ध लड़ रहे रूस को चारों तरफ से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। संकट की इस



‘सस्ते दाम पर रूस से और खरीदेगा तेल’

घड़ी में रूस की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा था लेकिन इस साल मार्च तक ही भारत रूस से 13 मिलियन बैरल तेल खरीद चुका है।

अमेरिका ने पिछले दिनों भारत को चेतावनी दी थी कि रूस से तेल की ज्यादा खरीद नई दिल्ली को महंगी पड़ सकती है।

दरअसल अमेरिका रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। फिलहाल अमेरिका ने दूसरे देशों के रूस से तेल खरीदने से मना नहीं किया है लेकिन सस्ते दाम पर ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों पर उसकी नजर

है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। पिछले साल भारत ने रूस से 16 मिलियन बैरल तेल खरीदा था लेकिन इस साल मार्च तक ही भारत रूस से 13 मिलियन बैरल तेल खरीद चुका है।

यही वजह रही कि रूस के विदेश मंत्री चीन के दौरे के बाद दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आए। चीन के विदेश मंत्री सर्गे लॉवरोव पर कोई दवाब काम नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहा है।

सीएम स्टालिन ने किया दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक का दौरा



राजेश अलख
नई दिल्ली, 01 अप्रैल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया।

एमके स्टालिन के साथ इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षा मंत्री मनीष सिंसोदिया भी मौजूद रहे। स्टालिन के साथ केजरीवाल और सिंसोदिया पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर स्थित राजकीय कन्या विद्यालय और मोहल्ला क्लीनिक पहुंचे। स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीएम स्टालिन ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की और सरकारी स्कूल में ईएमसी की क्लास में स्कूली छात्रों द्वारा विकसित बिजनेस आइडिया भी सुने। स्टालिन ने एक स्कूल में तैराकी की प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया।

ईएमसी क्लास का निरीक्षण के बाद सीएम स्टालिन ने दिल्ली सरकार के स्कूल के एक मॉडरेटी लैब का भी दौरा किया। वहीं दिल्ली सरकार की माने तो इस तरह की लैब के जरीवाल सरकार अगले 1 साल में 100 स्कूलों में बनाएगी। स्टालिन के इस दौरे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक का दौरा करने आए हैं। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं उन्हें अपने स्कूल और क्लीनिक दिखा रहा हूँ। सभी राज्यों को एक साथ काम करने और एक दूसरे से सीखने की जरूरत है तभी देश तरकी करेगा।

वहीं दिल्ली में इस दौरे को लेकर स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। तमिलनाडु

में मॉडर्न स्कूल कार्य किए जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि दिल्ली के सीएम उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे, राज्य के लोगों की ओर से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ।

गौरतलब है कि द्रमुक 2 अप्रैल को दिल्ली में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन को स्टालिन को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने के लिए एक प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है। इससे पहले द्रमुक संसदीय दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री टी.आर. बालू ने काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की और द्रमुक कार्यालय के उद्घाटन का भी निमंत्रण दिया था। इसके बाद शुक्रवार को स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को भी इस उद्घाटन समारोह में आने का निमंत्रण दिया है।

‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में छात्र-छात्राएं सहित अभिभावक भी काफी उत्साहित दिखे



गणेश सिंह ‘विशाल’
सिमरौली, 01 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘परीक्षा पे चर्चा’ के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ देश विदेश के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वचुअल बातचीत एवं चर्चा किया।

प्रधानमंत्री इस जीवंत कार्यक्रम में अपनी अनूठी व आकर्षक शैली में परीक्षा के तनाव से छात्रों को मुक्त करने, परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया। उपरोक्त कार्यक्रम विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य राजेश कुशवाहा के अध्यक्षता में वचुअल लाइव सहभागिता निभाते हुए केंद्रीय विद्यालय के 482 छात्र-छात्राएं एवं 78 अभिभावक, शिक्षकों,

कर्मचारियों ने विद्यालय में एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव देखा। विदित हो कि विद्यालय परिसर में सभागार सहित 4 स्थानों में एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से वचुअल लाइव देखने की व्यवस्था किया गया था। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक गण काफी उत्साहित देखे गए।

नेपाल के प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे



नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पत्नी आरजू राणा देउबा के साथ तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंचे।

अपनी इस यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में विशेष भोज का आयोजन करेंगे। देउबा इस दौरे में बिजनेस लीडर्स को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री देउबा के साथ उनका 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें विदेश, जल संसाधन, स्वास्थ्य, कृषि एवं फिजिकल प्लानिंग मंत्री, कारोबारी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के पुराने संबंधों को मजबूती देगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच साझेदारी कई क्षेत्रों में बढ़ी है। प्रधानमंत्री देउबा की इस यात्रा से दोनों पक्षों को इस साझेदारी की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा और साथ ही दोनों देशों के लोगों के हित के लिये इसे मजबूती देने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री देउबा विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जायेंगे, जहां वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा तथा अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे।

शाम में वह नयी दिल्ली स्थित नेपाल के दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वह भारत में रह रहे नेपाल के लोगों से बातचीत करेंगे।

शनिवार को प्रधानमंत्री देउबा नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत होगी। दोनों के बीच सीमा के मसले पर भी बात होगी।

प्रधानमंत्री देउबा अपनी यात्रा का समापन तीन अप्रैल को वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के साथ करेंगे। गौरतलब है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पी ओली की सरकार ने मई 2020 में एक नया मानचित्र जारी किया था जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिखिमयाधुरा क्षेत्र को नेपाल में दिखाया गया था, जिसके कारण दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गयी थी। इस बीच भारत ने सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला और रॉ प्रमुख समंत कुमार और साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच आधी इस कड़वाहट को दूर करने की कोशिश की।

बजाज फिनसर्व ने ‘सावधान रहें सेफ रहें’ अभियान लॉन्च किया

सिलीगुड़ी, 01 अप्रैल। भारत के सबसे बड़े फाइनेंसियल सर्विसेज प्रोवाइडर में से एक बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने ‘सावधान रहें। सेफ रहें।’ डिजिटल अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं और आम जनता को विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में शिक्षित करना है। यह अपने मुख्य नायक ‘गुप्ता जी’ के साथ एक और आकर्षक जिंजल के साथ आता है, जो उपभोक्ताओं को ‘ना जी ना जी ना जी’ के मंत्र का जाप करने की याद दिलाता है, जब भी जेनेरल इंश्योरेंस फ्रॉड के मामलों का सामना करना पड़ता है।

यह बजाज फिनसर्व लिमिटेड और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव है। अभियान उपभोक्ताओं को याद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण तोउचपोइंट पर प्रकाश डालता है जैसे (ए) हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों से पॉलिसी की जानकारी सत्यापित करें (बी) हमेशा कॉलर को सत्यापित करें और आकर्षक ऑफर के लिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को कभी न छोड़ें (सी) अविश्वसनीय बोनस या अज्ञात लोगों द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स के बहकावे में न आएं (डी) कभी भी एजेंसी/एजेंट को सीधे नकद में इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान न करें (ई) कभी भी बेहद कम प्रीमियम रेट्स के झांसे में न आएं (एफ) कभी भी ब्लॉक क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें या किसी एजेंट को पॉलिसी फॉर्म भरने की अनुमति न दें (जी) किसी तात्कालिकता या टाइट डेडलाइन्स से बंधे प्रस्तावों के झांसे में न आएं। इसमें सुरक्षित और संरक्षित रहने के लिए कुछ सुरक्षा युक्तियों और दिशानिर्देशों को भी सूचीबद्ध किया है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

अपस्टॉक्स ने लॉन्च किया ‘ओन योर फ्यूचर’ कैपेन

सिलीगुड़ी, 01 अप्रैल। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्मों में से एक अपस्टॉक्स (जिसे आरकेएसवी सिक्वोरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है) ने अपना इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 अभियान, ‘ओन योर फ्यूचर’ लॉन्च किया है। अभियान में हल्के-फुल्के वीडियो की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें बताया गया है कि ‘मेक योर फेब्रेट कम्पनीज वर्क फॉर यू’। अभियान का लक्ष्य युवा भारतीयों को इक्विटी बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, बुद्धिमानी से इन्वेस्टमेंट करना और समय के साथ बढ़ाने वाली एसेट का मालिक होना और उन्हें अपने भविष्य को कंट्रोल करने में मदद करना है।

सीरीज के पहले दो वीडियो टाइट आईपीएल 2022 के लॉन्च के साथ जारी किए गए थे। एक वीडियो में तीन दोस्तों के पुनर्मिलन को दिखाया गया है जहां वे अपने करियर के विकास पर चर्चा करते हैं। सीरीज का एक अन्य वीडियो एक मित्र के प्रचार पर चर्चा करने के लिए एक कैफे में दो दोस्तों के बीच मुलाकात को दर्शाता है। कंपनी के पास वर्तमान में 9 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और इसका लक्ष्य देश के दूरदराज के कोनों में रहने वाले उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना है। मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान में टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन शामिल हैं। अपस्टॉक्स की सह-स्थापक कविता सुब्रमण्यम ने कहा, ‘हम सकारात्मक हैं कि यह अभियान भारत में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की संस्कृति को चलाने में मदद करेगा, साथ ही अधिक भारतीयों को अपने वित्तीय भविष्य का प्रभार लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।’

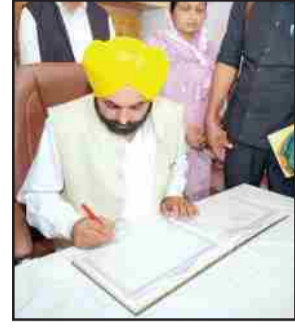
पठानकोट हमले के बाद सेना भेजने के बदले केंद्र ने पंजाब से मांगे थे 7.5 करोड़, भगवंत मान का सनसनीखेज आरोप

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पठानकोट हमले के दौरान सेना भेजने के एवज में केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से 7.5 करोड़ रुपये मांगे थे। पंजाब विधानसभा में बोलते हुए सीएम भगवंत मान ने पठानकोट हमले का जिक्र करते हुए ये बात कही। सीएम भगवंत मान ने कहा- मैं और आम आदमी पार्टी के नेता साधु सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास गए और हमने कहा कि आप ये पैसे हमें मिलने वाले संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड से काट लीजिए, बस बदले में हमें ये लिखकर दे दीजिए कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है और हम

सेना को किराए पर ले रहे हैं।

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद सेना तो बाद में पहुंची, सरकार की तरफ से चिट्ठी पहले आ गई कि पंजाब में सेना भेजी गई है इसलिए पंजाब को 7.5 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीएम भगवंत मान के भाषण का वो हिस्सा भी जारी किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि पठानकोट हमले के बाद केंद्र ने सेना भेजने के एवज में पंजाब से 7.5 करोड़ रुपये मांगे थे।

गौरतलब है कि साल 2016 में एक जनवरी की सुबह पाकिस्तान से आए चार आतंकीयों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था। इस आत्मघाती हमले में सेना के



सात जवान शहीद हो गए थे। करीब 80 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने चारों आतंकीयों को मार गिराया था। पठानकोट हमले का जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकीयों के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था।

अगर भारत कुछ भी खरीदना चाहता है तो हम चर्चा के लिए तैयार है : रूसी विदेश मंत्री

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच भारत पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि भारत कुछ खरीदना चाहता है तो हम चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस के रूस ने भारत जैसे देशों के साथ राष्ट्रीय मुद्दाओं में व्यापार करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है और डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली से दूर जाने के प्रयास तेज होंगे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के बाद एक संवादाता सम्मेलन में उन्होंने कहा राष्ट्रीय मुद्दाओं का उपयोग करके और डॉलर आधारित प्रणाली को दरकिनार करते हुए अधिक से

अधिक लेनदेन किए जाएंगे। लावरोव ने कहा कि भारत के साथ व्यापार के लिए एक रुपया-रुबल भुगतान प्रणाली पहले ही लागू की गई थी और इसे और मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि रूस के केंद्रीय बैंक ने कई साल पहले वित्तीय सूचनाओं के संचार के लिए एक प्रणाली स्थापित की थी और भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्ली और मास्को व्यापार को सुविधाजनक बनाने और रूसी बैंकों पर पश्चिमी प्रतिबंधों के आसपास एक रुपया-रुबल सिस्टम पर काम कर रहे हैं।

रियायत के साथ रूसी तेल खरीदने की भारत की योजना के

बारे में पूछे जाने पर लावरोव ने कहा कि मास्को कुछ भी देने के लिए तैयार है जो नई दिल्ली खरीदना चाहता है। हम दोस्त हैं। बता दें कि रूस भारत को रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और लावरोव ने कहा कि दोनों देश तेल, सैन्य हार्डवेयर और अन्य सामानों के व्यापार के लिए रुपए-रुबल सिस्टम का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा, ‘मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृत्रिम बाधाओं को दूर करने के लिए एक रास्ता (पाया गया) होगा जो पश्चिम द्वारा अवैध एकतरफा प्रतिबंध पैदा करता है। यह सैन्य-तकनीकी सहयोग के क्षेत्र से भी संबंधित है। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है।’

आज से महंगी हुई 800 से ज्यादा दवाएं, राज्यसभा में माकपा सांसद जॉन ब्रिटस ने उठाया मामला

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। माकपा के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटस ने शुक्रवार को सरकार से आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने का आग्रह किया।

शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाते हुए, केरल के सांसद ने कहा: ‘आम आदमी का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। लोग पहले से ही कीमतों में बढ़ोतरी से जूझ रहे हैं और हर दिन ईंधन की दरें बढ़ रही हैं। दुर्भाग्य से, 800 से अधिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 11 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है।’

ब्रिटस ने कहा: ‘यह अभूतपूर्व है क्योंकि कीमतों में इतनी तेज वृद्धि कभी नहीं हुई है। जब पूरा देश स्वास्थ्य आपातकाल से गुजर रहा



है, तो किसी भी संवेदनशील सरकार को इससे बचना चाहिए। लेकिन लोगों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है।’

उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले साल की वृद्धि सिर्फ 0.53 प्रतिशत थी और 2020 में यह 1.88 प्रतिशत हो गई।

ब्रिटस ने कहा, ‘पिछले वर्षों

में कीमतों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई थी। मैंने सरकार से आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने का आग्रह किया है।’

शिवसेना सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जीवन यापन की लागत हर दिन बढ़ रही है और सरकार को लोगों को कुछ राहत देने पर विचार करना चाहिए।

झूठी शान की खातिर हत्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह झूठी शान की खातिर की गई हत्या (ऑनर किलिंग) के मामले को हल्के में नहीं लेगा। साथ ही, एक महिला को उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसने मामले में अपने चाचा की जमानत रह करने का आग्रह किया है। दरअसल, महिला के अंतर-जातीय विवाह करने पर पिछले साल उसके पति की हत्या की साजिश में उसका चाचा कथित रूप से संलिप्त था।

राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करने से पहले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दीप मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता एमएसए अर्थ से कड़े सवाल किए। दीपि के पति की पिछले साल कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में महिला के चाचा के

खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं थे, जिसमें केवल यह कहा गया था कि उसने शादी का विरोध किया था।

अधिवक्ता ने कहा कि दीपि के चाचा मणिकांत मिश्रा और उनके दो बेटे हमले में शामिल थे तथा पूर्व में भी ऐसी (हमले की) घटनाएं हो चुकी थीं, जिस पर महिला के पति द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

पीठ ने कहा, ‘यह झूठी शान की खातिर हत्या का मामला है और हम इसे हल्के में नहीं लेते।’ शारी का विरोध किया था। कोई विशेष आरोप नहीं है। प्राथमिकी में यह नहीं कहा गया है कि वह घटना के समय वहां मौजूद था या वह साजिशकर्ता था।’

सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन आर्य ने पीठ को मनाने की कोशिश की और हत्या की घटना से ठीक पहले धमकी और हमले की घटनाओं की महिला के पति (मृतक) द्वारा सूचना दिए जाने को रेखांकित किया। पीठ ने कहा, ‘ठीक है, हम नोटिस जारी करेंगे। प्रतिवादी संख्या दो (मणिकांत मिश्रा) को नोटिस स्थानीय पुलिस थाने के माध्यम से दिया जाना चाहिए।’

दीपि द्वारा वकील सी के राय के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, यह मामला झूठी शान की खातिर हत्या से संबंधित है, जिसमें उसके पति को महिला के रिश्तेदारों ने केवल इसलिए मार डाला कि वह धोबी जाति का था और उसकी शादी एक ब्राह्मण लड़की से हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 17 दिसंबर को मणिकांत को जमानत दे दी थी।

युद्ध के समय भारत

भारत इन दिनों जितने दबाव में है, उतनी ही मांग में भी है। दुनिया के अनेक आला देशों के आला अधिकारियों व नेताओं ने भारत की ओर रुख कर रखा है। विशेष रूप से जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से भारत में किसी न किसी विदेश मंत्री या विदेश सेवा के अधिकारी की मौजूदगी देखी जा रही है। भारत की तटस्थ स्थिति ने दुनिया की महाशक्तियों को बेचैन कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूक्रेन का पक्ष तो लिया है, लेकिन वह रूस के खिलाफ भी नहीं गया है। ऐसे में, यह धारणा फैल गई है कि भारत को जिस तरह से नाटो का साथ देना चाहिए, वह नहीं दे रहा है। अतः भारत न केवल अमेरिका की ओर से, बल्कि यूरोपीय देशों की ओर से भी दबाव में है। अमेरिका, रूस, चीन, मैक्सिको, नीदरलैंड, ब्रिटेन इत्यादि देशों के कूटनीतिज्ञ भारत पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अपनी-अपनी ओर इसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यह महज संयोग नहीं है कि जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेस लावरोव भारत यात्रा पर हैं, तब अमेरिका के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह भी भारत में मौजूद हैं। रूस भारत से मदद चाहता है, तो अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत किसी भी तरह से रूस की मदद करे, और रूस की भी कोशिश है कि वह भारत को युद्ध में नाटो के साथ खड़ा होने से रोके। दुर्दिन में भी भारत ने रूस से तेल खरीदने की मंजूरी देकर पिछले दिनों जो धमाका किया था, उसकी गूंज दुनिया में अभी भी है। अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों ने यही समझा कि भारत पिछले दरवाजे से रूस की मदद करते रहना चाहता है, क्योंकि रूस उसका पुराना साथी है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन अब रूस के साथ लगभग शाब्दिक रूप से खुलकर खड़ा हो गया है। ध्यान रहे, रूसी विदेश मंत्री चीन से होते हुए ही भारत आए थे। चीनी विदेश मंत्री भी हाल ही में भारत आए थे और भारत को अपने ढंग से मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस आपाधापी में चीन बिना किसी समझौते या रियायत के भारत के साथ व्यवसाय करते रहना चाहता है। इस मामले में रूस और अमेरिका कुछ अलग हैं, दोनों देशों के पास भारत को रिझाने के लिए कुछ न कुछ है। तेल, तकनीक, आईटी, शिक्षा, व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक लिहाज से भी अमेरिका अब भारत के ज्यादा करीब है। कभी रूस के प्रति भी भारत में बहुत लगाव था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के समय रूस ज्यादातर मौकों पर चीन के साथ खड़ा दिखा है और भारत से कुछ दूरी भी बनी है।

जाहिर सी बात है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त देश के व्यस्ततम लोगों में शुमार हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आज तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में अपना देश निर्णायक मोड़ पर है। बहुत सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी विदेशी नेता या अधिकारी के दबाव में न आते हुए, अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखना है। यह युद्ध के चलते पीड़ित हो रहे देशों और उनके लोगों के प्रति संवेदना का समय है। युद्ध की निंदा और यूक्रेन की मदद में कोई कौर कसर न रहे, तो दुनिया भारत के पक्ष को समझेगी। किसी भी स्थिति में भारत को युद्ध में कूदने से बचना चाहिए।

युद्ध विरोध की भावना और मानवता का दामन थामे हुए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में भारत प्रेमियों की तादाद बढ़े, भारत विरोधियों की नहीं।

संवादकीय पृष्ठ

श्रीलंका में संकट की लंबी कतारें

संदन जयवर्द्धना उधर सूरज ढल रहा है और इधर अपनी लॉरी में बैठे दयारत्ने अपना गुस्सा छिपा नहीं पा रहे हैं। वह सुबह से ही कोलंबो के बाहरी इलाके कडुवेला के एक पेट्रोल-डीजल पंप पर लंबी कतार में लगे हैं। यहां अब आम लोग बोलने लगे हैं कि इस सरकार को परवाह नहीं है और देश गलत हाथों में चला गया है। दयारत्ने देश की राजधानी से 350 किलोमीटर दूर पहाड़ी गांव बादुल्ला से हैं। वह एक स्थानीय कंपनी के लिए आपूर्ति का काम करते हैं। उनके तीन स्कूली बच्चे हैं। दयारत्ने जो कुछ कमाते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। वह कहते हैं, मैंने एक साथ 5,000 रुपये निकाले हैं और आज ही अपने परिवार को भेज दिए हैं, ताकि अगले कुछ दिनों तक परिवार संकट का सामना न कर सके। मैं तब तक काम नहीं कर सकता, जब तक मुझे डीजल नहीं मिल जाता। मैंने पहले ही परिवार वालों से कह दिया है कि वे किसी तरह चावल और नारियल के सांबोले से काम चलाएं, क्योंकि हम और अधिक खर्च नहीं कर सकते।

यहां ऑटोरिक्षा चालकों का समूह भी सरकार की निंदा कर रहा है। किराया बढ़ गया है, तो सवारियां मिल नहीं रही हैं। आर्थिक आपदा के चलते लोग गंभीर संकट में हैं। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किराया बढ़ाना पड़ा है, जिससे काम आधा ही रह गया है। लोग पैसे बचाने के लिए कम दूरी की यात्राएं पैदल ही तय करने लगे हैं। युवा सवालोंने से भरे हुए हैं कि राष्ट्रपति भला क्या कर रहे हैं? लोग

राष्ट्रपति की शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वादों के बावजूद प्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई है। श्रीलंकाई लोगों का जीवन गंभीर आर्थिक उथल-पुथल से प्रभावित हो रहा है। भारी कर्ज, खराब नीति नियोजन, कोविड-19 महामारी और हाल ही में यूक्रेन में युद्ध के संयोजन के कारण देश में एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट पैदा हो गया है। चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। डीजल, मिट्टी के तेल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और यहां तक कि दवाओं की भी भारी कमी हो गई है।

पिछले कुछ हफ्तों में संकट चरम पर पहुंच गया है। बिजली उत्पादन हाइड्रो, थर्मल और कोयला क्षमता पर निर्भर करता है। चूंकि यह शुष्क मौसम है, जलाशयों में जल स्तर तेजी से घट रहा है और पानी खेती के लिए संरक्षित किया जा रहा है, जिससे डीजल से चलने वाले संयंत्रों पर भारी निभरता हो गई है। ईंधन खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर नहीं है, तो फरवरी महीने से जारी कुछ घंटों की बिजली कटौती 31 मार्च से 13 घंटे की कर दी गई है।

ईंधन और गैस सिलेंडर की दुकानों पर मीलों लंबी कतारें रोजमर्रा की बात हो गई हैं। गुस्सा उबल रहा है और छोटी-छोटी बातों पर भी लड़ाई छिड़ जा रही है। हाल ही में कतार तोड़ने वाले एक 29 साल के मोटोसाइकिल चालक की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। बुजुर्गों के लिए तनाव विशेष रूप से घातक है, मार्च में चार की गिरकर मौत हुई है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर सशस्त्र

सैनिकों को तैनात किया गया है। कर्मचारियों के पास काम पर जाने के लिए ईंधन नहीं है और घर से काम करने के लिए बिजली नहीं है। डीजल की कमी के चलते लंबी दूरी की कई बसों ने परिचालन बंद कर दिया है। विरोध प्रदर्शन अब स्वतःस्फूर्त हो रहे हैं। विपक्ष दलों ने राष्ट्रपति राजपक्षे घर जाओ का आह्वान करते हुए बड़े पैमाने पर रैलियां की हैं। सोशल मीडिया पर गोय गो बैक और गो होम राजपक्षे जैसे हेशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में बड़ी विरोध सभा की उम्मीद है।

श्रीलंका की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अकेले इस वर्ष देश का विदेशी ऋण दायित्व 6.69 अरब डॉलर है। इसमें से एक अरब जुलाई में लौटना है। इधर पर्यटकों का आना भी बहुत कम हो गया है। विदेश काम करने वाले वालों की संख्या सबसे कम हो गई है। राजपक्षे प्रशासन ने विनाशकारी नीतिगत फैसलों से स्थिति को और खराब कर दिया है। नवंबर 2019 में राष्ट्रपति राजपक्षे की जीत के बाद शुरू की गई व्यापक कर कटौती ने खजाने को तहस-नहस कर दिया है।

मई 2021 में श्रीलंका ने कृषि-रसायनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, यह कदम श्रीलंका को 100 प्रतिशत जैविक कृषि वाला दुनिया का पहला देश बनाने के लिए उद्योग गया था। यह कृषि के लिए घातक रहा और सरकार अंततः पीछे हट गई, लेकिन अब उपज बहुत कम हो गई। कई किसानों ने खेती छोड़ दी है। कृषि रसायन बाजार में लौट आए हैं, पर अब वे बिना सब्सिडी बहुत महंगे हैं। मुद्रा की खूब छपाई

हो रही है, जिससे महंगाई और बढ़ रही है। 30 मार्च को अमेरिकी डॉलर 299 श्रीलंकाई रुपये में बिक रहा था।

प्रशासन की अपनी आंतरिक समस्याएं भी खूब हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे ने हाल ही में अपने भाई, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के चलते दो मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। जिन मंत्रियों को हटया गया है, वह सरकार को उखाड़ फेंकने की कसमें खा रहे हैं।

कई महीनों से आब्रजन विभाग के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। लोगों को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। अधिक हाताश लोग अन्य मार्गों से भागने की कोशिश कर रहे हैं।

22 मार्च को 16 पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक नाव से तमिलनाडु पहुंचे हैं। लोग भुखमरी से भाग रहे हैं। उन्हें इससे बुरा समय याद नहीं है। लोग रोज जो कमाते हैं, उसका लगभग तीन-चौथाई भोजन पर खर्च हो जाता है। सरकार की अब तक की रणनीति बांग्लादेश, भारत और चीन से अल्पकालिक द्विपक्षीय ऋण लेने की रही है। भारत ने हाल ही में दवाओं, ईंधन और भोजन के लिए श्रीलंका को एक अरब डॉलर का कर्ज दिया है।

इस सप्ताह भारत से और एक अरब डॉलर अतिरिक्त ऋण की मांग की गई है। दो साल तक विरोध के बाद राष्ट्रपति ने इस महीने पुष्टि की है कि वह वित्तीय सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करेंगे। हालांकि, इनमें से कोई भी त्वरित समाधान नहीं है, जिसकी श्रीलंका को अभी सख्त जरूरत है।

फैसलों का लंबा खिंचता इंतजार

मुकुल श्रीवास्तव विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था में जेल (कारागार) किसी भी अपराध का दंड है। यानी जेल, तंत्र का वह अंग है, जो इस दर्शन पर आधारित है कि अपराधियों को समाज से दूर रखकर एक ऐसा वातावरण दिया जाए, जहां वे आत्म चिंतन कर सकें। पर क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? सरकार ने लोकसभा में 25 मार्च को जानकारी दी है कि देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मुकदमे अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित हैं। देश की 25 उच्च अदालतों में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं।

इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है। इनमें से कुछ मामले पचास साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वे आंकड़े बताते हैं कि भारत में जेल सुधारों की त्वरित आवश्यकता है। जिसका एक बड़ा कारण लंबित मुकदमों का बढ़ना, न्यायाधीशों की कमी और सभी जेलों का क्षमता से ज्यादा भरा होना है। जिसका परिणाम कैदियों के खराब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के

रूप में आ रहा है। जेल में यंत्रणा आम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट जेल सांख्यिकी भारत 2020' के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की जेलों में बंद हर चार में से तीन कैदी ऐसे हैं, जिन्हें विचाराधीन कैदी के तौर पर जाना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो इन कैदियों के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनकी सुनवाई अदालत में चल रही है। अभी तक इनके ऊपर लगे आरोप सही साबित नहीं हुए हैं। रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि देश की जिला जेलों में औसतन 136 प्रतिशत की दर से कैदी रह रहे हैं।

इसका मतलब यह है कि 100 कैदियों के रहने की जगह पर 136 कैदी रह रहे हैं। फिलहाल, भारत की 410 जिला जेलों में 4,88,500 से ज्यादा कैदी बंद हैं। 2020 में, जेल में बंद कैदियों में 20 हजार से ज्यादा महिलाएं थीं, जिनमें से 1,427 महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी थे। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी

इंटरनेशनल ने कहा कि भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या दुनिया भर के अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 और 25 उच्च न्यायालयों में 1,098 है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर, 2021 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 898 फास्ट ट्रेक अदालतें काम कर रही हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, उस समस्या के हल का एक पक्ष हो सकता है, जो भारत की खराब जेल व्यवस्था का एक बड़ा कारण है। जजों की संख्या कम होने से जेल में लंबित कैदियों की संख्या बढ़ती जाती है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की जेलों में बंद 69 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं। यानी भारत की जेलों में बंद हर दस में से सात कैदी मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के इंतजार में हैं। इस समस्या के सामाजिक-आर्थिक पक्ष भी हैं। देश

में गरीब व्यक्ति के लिए इंसाफ की लड़ाई ज्यादा कठिन है। जिन्हें अच्छे और महंगे वकील मिल जाते हैं, उनकी जमानत आसानी से हो जाती है। दूसरी ओर बहुत मामूली से अपराधों के लिए भी गरीब लोग लंबे समय तक जेल में सड़ने को विवश होते हैं।

आपराधिक मुकदमों में ज्यादातर के पूरा होने में औसत रूप से तीन से दस साल का समय लगता है, हालांकि दोषसिद्धि का समय मुकदमों के लिए जेल में बिताए समय से घटा दिया जाता है, लेकिन इसकी वजह से कई निर्दोषों को बगैर किसी अपराध के जेल की सजा काटनी पड़ती है।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ राय की अध्यक्षता वाली समिति देश भर की जेलों की समस्याओं को देख रही है और उनसे निपटने के उपाय सुझा रही है। मार्च की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को अगले छह माह में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। तब तक जेलों में बंद कैदियों का इंतजार जारी रहने वाला है।

गरीबों को मुफ्त अनाज

रवि शंकर केंद्र सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएआई) को इस साल सितम्बर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 थी लेकिन अब अब इसे 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाया गया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह 30

सितम्बर तक इसका लाभ उठा सकेंगे। इस योजना पर सरकार की ओर से सितम्बर तक होने वाले खर्च की बात करें तो यह 3.40 लाख करोड़ रुपये होगा।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान के लॉकडाउन में रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे लोगों के लिए सरकार ने मार्च, 2020 में मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलता है और करीब 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन दिया जाता है। अब तक

खाद्य मंत्रालय ने कुल 759 लाख टन खाद्यान्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित किया है।

बहरहाल, सरकार के इस फैसले से करीब 80,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर आएगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने अपने पहले फैसले के तहत मुफ्त अनाज मुहैया कराने का समय तीन माह बढ़ाकर 30 जून, 2022 तक कर दिया है। दोनों ही फैसले बेहद मानवीय हैं क्योंकि कोरोना महामारी के 24 महीनों के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। करीब 25 करोड़ लोग गरीबी-रेखा के तले

जीवन जीने को विवश हैं। यह आज की विकराल समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी की राष्ट्रीय दर 8 फीसदी से अधिक है। जिनके रोजगार आपदा के दौर में छिन गए थे, उनकी 100 फीसदी बहाली में कितना वक्त लगेगा, शायद सरकारों के पास भी सटीक आकलन नहीं हैं।

हालांकि भारत सरकार में आर्थिकी से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के सुझाव थे कि कोरोना-पूर्व की अर्थव्यवस्था की पूर्ण बहाली के लिए अब मुफ्त अन्न योजना बंद कर देनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सुझाव को सिरे से नकार दिया। उन्हें गरीब तबकों की

अस्थिर और अनिश्चित स्थिति

कुलदीप तलवार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब आठ महीने बाद भी वहां की स्थिति अस्थिर और अनिश्चित बनी हुई है। अभी तक शासन के ऐसे ढांचे का गठन नहीं हो पाया है, जो विविधता दर्शा सके और उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। दूसरी बार सत्ता पर काबिज होते हुए तालिबान ने यह संकल्प जताया था कि वे महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों में कटौती नहीं करेंगे और उन्हें बराबरी का अधिकार देंगे। विगत 23 मार्च को तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर लगी पाबंदी उठा भी ली।

उन्होंने छठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों के स्कूल खोलने का भी हुक्म दे दिया, लेकिन इस घोषणा के चंद घंटे बाद ही फिर उसे वापस ले लिया। उसके बाद तालिबान ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक इस्लामी शरिया कानून व अफगान संस्कृति के अनुसार योजना तैयार नहीं हो जाती। जाहिर है, छात्राओं की खुशी कुछ ही पल में निराशा में बदल गई। संयुक्त राष्ट्र व अमेरिका ने अपने वायदे से मुकरने पर तालिबान को कड़ी आलोचना की है।

इससे तालिबान ने पिछले आठ महीने में जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश की थी, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अफगानिस्तान में अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालय बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए महिलाएं व लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ प्रांतों में निजी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन उन पर भी तालिबान ने ड्रेस संबंधी कुछ शर्तें लाद दी हैं। अब अफगानी लड़कियों को बुरका और लड़कों को अफगानी पोशाक पहनकर जाना होगा और उन्हें अलग-अलग बैठकर पढ़ाई करनी होगी।

इससे देश की छात्राएं ही नहीं, बल्कि छात्र भी परेशान हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी प्रदर्शनकारी महिलाओं को चुपचाप रात को उनके घर से उठा लिया जाता है।

हाल ही में जब उन्होंने शिक्षा का अधिकार पाने के लिए तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो उन्हें खदेड़ने के लिए मिर्च पाउडर और बिजली के झटके का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तालिबान ने प्रदर्शन की मुखिया तमना जरायानी के घर घुसकर उसकी दो बहनों को उठा लिया, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है।

तालिबान सरकार ने कामकाजी महिलाओं को भी आदेश दिया है कि वे अपने शरीर को पूरी तरह ढककर ही दफ्तर जाएं, वरना उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। असल में, तालिबान महिलाओं के नौकरी के हक में नहीं है। आईएलओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सन 2021 की तीसरी छमाही में महिलाओं के रोजगार में सोलह प्रतिशत की कमी आई है और 2022 के मध्य तक इसके 28 प्रतिशत पहुंचने की आशंका है। तालिबान के पहले दौर के शासन को छोड़कर अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और शिक्षा पर पाबंदी जैसी कोई बात नहीं थी।

महिलाएं विश्वविद्यालयों में अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर जाती थीं। उन्हें साइकिल चलाने और पुरुषों के साथ चलने की आजादी थी। सरकारों ने महिलाओं की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अधिकार की सांविधानिक सुरक्षा दी गई थी। सोवियत संघ और कुछ अन्य देशों में महिलाओं को स्कॉलरशिप देने के लिए सिफारिश की जाती थी। डॉ. नजीबुल्ला की सरकार के खतमे तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन तालिबान के पहले दौर में लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए गए और उन पर तरह-तरह के अत्याचार ढाए गए।

फिर करजई और अशरफ गनी की सरकार ने भी महिलाओं के हक में कई कदम उठाए, लेकिन अब फिर महिलाओं को शिक्षा पर पाबंदी लगी है। यही नहीं, तालिबान ने देश से बाहर जाने वाली उड़ानों में महिलाओं के अकेले सफर पर रोक लगा दी है। उन्हें रोजगार से भी वंचित किया जा रहा है।

देश में बेरोजगारी फैली हुई है और लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अगर लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया और उनकी राह में बाधाएं खड़ी की गई, तो अफगानिस्तान के हालात बंद से बदतर हो जाएंगे। कोई भी देश तालिबान शासन को मान्यता नहीं देगा।

नाजुक स्थिति का पता है, और वे किसी सूरत नहीं चाहते कि गरीबों को उनके हाल पर छोड़ा जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की अवधि बढ़ाने का निर्णय फैसला किया। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि महामारी के बाद रूस-यूक्रेन संकट के बीच जहां एक तरफ दुनिया भर में अनाज की सफ़लाई पर असर पड़ रहा है, वहीं भारत न केवल दुनिया भर के कई देशों को गेहूँ का निर्यात बढ़ा रहा है, बल्कि मोदी सरकार देश के लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध भी करा पा रही है। केंद्र सरकार ने इस पर कहा है कि आम लोगों को जरूरत के दौरान मुफ्त राशन मुहैया कराना सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि महामारी के बीच भी किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न की खरीद की गई है। सरकार पहले की कह चुकी है कि फसलों की ऊंची कीमतें मिलने से न केवल खरीद बढ़ी है वहीं किसान उत्पादन और बढ़ाने के लिए भी प्रेरित हुए हैं। सरकार ने कहा है कि मुफ्त अनाज का योगदान बढ़ाने का यह फैसला किसानों की वजह से संभव हुआ है। वहीं माना जा रहा है कि फिलहाल सरकार के अन्न भंडार भरे हुए हैं, और आने वाले समय में फिर से रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद

की जा रही है। इसलिए सरकार के पास फिलहाल योजना को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी।

कोविड-19 महामारी ने पूरे देश को कई तरह से प्रभावित किया है। इसने लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाया है। इसने समाज के सबसे कमजोर तबके को झकझोर कर रखा दिया। लेकिन ऐसी निराशाजनक हालात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से इन लोगों को बड़ी राहत मिली। हालांकि इस योजना पर राजनीतिक तौर पर संदेह भी व्यक्त किए जा रहे थे कि चुनावों के बाद इसे समाप्त किया जा सकता है अथवा कुछ कटौतियां संभव हैं! संदेह गलत साबित हुए।

बहरहाल, केंद्र और राज्य, दोनों के स्तर पर गरीबों को कम्बोवेश भुखमरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। यदि छह माह के दौरान वितरित किए जाने वाले अनाज को भी जोड़ दिया जाए तो सरकार 1003 लाख मीट्रिक टन अनाज निःशुल्क ही गरीबों को मुहैया करा देगी। यह मात्रा अभूतपूर्व है। अब तक इस योजना पर सरकार 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और अगले छह महीनों में इस पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।



सब्जी के पौध रोपण को अच्छा बनाने के लिए व हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए नेथेलिन एसिटिक एसिड, इण्डोल एसिटिक एसिड के द्वारा जड़ों को 0.1-0.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर 24 घंटे तक उपचारित करें यह टमाटर, बैंगन व गोभीवर्गीय फसलों में लाभदायक होता है.

सब्जियों को दे उन्नत तकनीक की खुराक

लम्बी अवधि वाले पौधों में शीघ्र पुष्पन

आलू, पालक, मिर्च इत्यादि में जल्दी ही फूल आ जाते हैं जिबरेलिक एसिड 200-800 पी.पी.एम सांद्र घोल से छिड़काव करना चाहिए व 2.4 डी के 100 पी.पी.एम. घोल का शकरकंद के ऊपर छिड़काव करने से फूल जल्दी आ जाते हैं. सब्जी के पौध रोपण को अच्छा बनाने के लिए व हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए नेथेलिन एसिटिक एसिड, इण्डोल एसिटिक एसिड के द्वारा जड़ों को 0.1-0.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर 24 घंटे तक उपचारित करें यह टमाटर, बैंगन व गोभीवर्गीय फसलों में लाभदायक होता है. सब्जियों को बहुत अधिक सर्दी से बचाने के लिये 0.75 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर साइकोसिल (सी.सी.सी.) का छिड़काव कलिका बनने से पहले आलू की फसल में करने से पौधों में अधिक सर्दी को सहन करने की क्षमता आ जाती है. टमाटर में 0.4 से 0.5 प्रतिशत साइकोसिल और जिबरेलिक एसिड 25 पी.पी.एम. के छिड़काव से इसे सर्दी के प्रति कठोर बनाया जा सकता है. मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने (जिनमें नर व मादा फूल अलग-अलग आते हैं - जैसे कुकरबिटेरी कुल के पौधों में व खीरा, लौकी में जिबरेलिक एसिड का 10-30 पी.पी.एम. घोल का छिड़काव हो जाता है. जिससे मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हो जाती है व उपज भी बढ़ जाती है इसके अतिरिक्त खीरा तथा लौकी में मौलिक हाइड्रॉक्साइड के दो छिड़काव 25 से 50 पी.पी.एम. दो या चार परती अवस्था में करना चाहिए जिससे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है व उपज में वृद्धि हो जाती है. फलों को सुचारु रूप से बनने तथा विकास को नियमित करने में - टमाटर, मिर्च के लिये नेथेलिन एसिटिक एसिड का 20 पी.पी.एम. तथा बैंगन के लिये इण्डोल एसिटिक एसिड 50-100 पी.पी.एम के घोल का छिड़काव करें जिससे फलों का विकास अच्छी प्रकार से होता है.

पार्थेनोकार्पी व फलों के विकास में - बैंगन तथा कुकरबिटेस में 2.4 डी 25-30 पी.पी.एम. व नेथेलीन एसिटिक एसिड 200 पी.पी.एम. के घोल का छिड़काव करने से बीज रहित फल का निर्माण होता है. फलों को एक समान पकाने व रंग लाने के लिये - टमाटर को 1000 पी.पी.एम. व मिर्च को 2000-5000 पी.पी.एम. से दो मिनट तक उपचारित करने से फल एक समान पकते हैं व समान रंग आता है जिससे बाजार मूल्य अच्छा मिलता है.

पौध वृद्धि हार्मोन्स

पादप हार्मोन्स एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो परिवहन पश्चात पादपों के अन्य अंगों में पहुंचकर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि तथा उपापचय क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं. इन्हें पादप हार्मोन्स कहा जाता है. इसको निम्न दो वर्गों में बाँटा गया है :-

आक्जिन	इथाइलीन
अ. इण्डोल एसिटिक एसिड, ब. इण्डोल ब्यूटाइरिक एसिड, स. नेथेलिन एसिटिक एसिड	पौध वृद्धि नियामकों का सब्जी उत्पादन में लाभदायक प्रयोग -
जिबरेलिक	प्रसुसा अवस्था तोड़ने
अ. जिबरेलिक एसिड साइटोकाइनिन - काइनेटिन, जिपेटिन वृद्धि रोधक एबीसीएसिक एसिड	(अ) आलू फसल में यदि एक प्रतिशत याथेयूरिया, इथाइलीन क्लोराइड या जिबरेलिक एसिड का उपयोग करते हैं तो प्रसुसावस्था को तोड़ा जा सकता है. (ब) आलू को बुवाई पूर्व जिबरेलिक एसिड 0.5 मि.ग्रा. प्रति लीटर व बैंगन में 15-25 पी.पी.एम. तथा लौकी, खरबूजा और तरबूज इत्यादि को एथोफान 500 पी.पी.एम. से 24 घंटे तक बीज को बुवाई से पहले भिगोये.

पाला से बचाने के लिये

टमाटर व पालक को पाला से बचाने के लिये एसिटिक एसिड का खीरा में जिबरेलिक एसिड 1 पी.पी.एम. का उपयोग किया जाता है. सॉडियो (टमाटर, मिर्च) के पौधों में फलों के गिरने से बचाने के लिये प्लेनोफिक्स 10-20 पी.पी.एम. घोल का छिड़काव करें जिससे फलों को गिरने से रोका जा सकता है. प्याज में इथियान की 500-1000 पी.पी.एम. की 4-5 पत्ती अवस्था में प्रयोग करने से प्याज की गोढ़ बनना शीघ्र प्रारंभ हो जाती है. चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण में 2.4 डी का छिड़काव किया जाता है. उपरोक्त मात्रा को किसान भाई सही मात्रा व सही समय पर प्रयोग करके सब्जियों के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

पौध वृद्धि नियामकों के प्रयोग के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ

- अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करने पर यह ड्रेपडू की वृद्धि एवं विकास के साथ-साथ गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालता है.
- इनका प्रयोग सही अनुपात में करना चाहिए अन्यथा यह सिंक एवं सोर्स के संबंध पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं. जिससे ड्रेपडू का गिरना तथा विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने की संभावना बढ़ जाती है.
- यह महंगे होते हैं और बाजार में आसानी से नहीं मिल पाते हैं. जिससे किसान इसका प्रयोग अपनी फसलों की उपज बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं.

प्रदूषित मिट्टी की पहचान एवं समाधान

मिट्टी को उपजाऊ बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि उसे क्षरण और प्रदूषण से बचावें। परंतु उससे पहले यह जानना होगा कि क्या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से उत्पादकता कम हो रही है या प्रदूषण में जमा हो रहे पदार्थों से उर्वराशक्ति क्षीण हो रही है और यदि मिट्टी में प्रदूषित हो रही है तो उसके कारकों को जाने उर्वर प्रबंधन करें अन्यथा मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा जिसके कारण वर्तमान समय में नई-नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। कुछ प्रदूषण के कारक निम्नानुसार हैं:



कृषि रसायनों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण: परंपरागत खेती में मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्र मिट्टी-पौधे-पशु-मिट्टी होता था जो आज की आधुनिक खेती में रसायनिक उर्वरकों के कारण छोटा हो गया है इस कारण पौधे/पशु अवशेषों से मिट्टी में प्रदूषण बढ़ है गुणवत्ता बढ़ाने के स्थान पर प्रदूषित करते हैं। कृषि में प्रयोग किये जाने वाले कृषि रसायनों द्वारा प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है।

(अ) रसायनिक कीटनाशियों में मुख्य रूप से दो प्रकार के कीटनाशी प्रयोग किये जाते हैं। वे निम्न हैं

ओरगेनोक्लोरीनस

ये कीटनाशी मिट्टी में जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं जिसके कुछ अंश वर्षों तक मिट्टी में विद्यमान रहते हैं जिनके कारण हार्मोन्स एवं एंजाइम्स की क्रियाएँ परिवर्तित हो जाती हैं जिससे उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि।

ओरगेनोफास्फेट

ये मिट्टियों में अधिक मात्रा में प्रयोग किये जाते हैं परंतु जीवाणुओं द्वारा जल्दी अपघटित हो जाते हैं और जीव-जंतुओं के शरीर में संचित नहीं होते हैं।

- फफूंदनाशकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण: पारयायुक्त रसायनों के उपयोग से मृदा के लाभकारी जीवाणुओं को हानि पहुंचाते हैं जो मिट्टी के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इन पर भारत शासन द्वारा 1996 में प्रतिबंध लगा दिया है जैसे - एग्रीसान, मोनोसान बीजोपचारक दवाओं द्वारा मिट्टी प्रदूषण होता है।
- खरपतवार नाशकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण: खरपतवार नाशी मिट्टी परिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं साथ ही प्रकाश सश्लेषण की क्रिया पर भी सीधा कुप्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवारशी रसायन दलहन मिट्टी जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं।

दोस एवं जलीय अपद्रव्यों द्वारा

दोस एवं जलीय अपद्रव्य मिट्टी में निम्नलिखित स्त्रोतों द्वारा मिट्टी में पहुंच कर मिट्टी की उर्वराशक्ति को क्षीण करती हैं।

- कारखानों के अपद्रव्यों द्वारा प्रदूषण: फेक्ट्रियों एवं कारखानों से निकली दोस एवं जलीय अपद्रव्यों को बिना उपचारित किये मिट्टी में विसर्जित करना मिट्टी एवं फसल दोनों को घातक है इनमें विषैले तत्व मिले होने के कारण मिट्टी की उर्वराशक्ति पर घातक प्रभाव डालती है। इन दोस एवं जलीय अपद्रव्यों से मिट्टी की भौतिक, रसायनिक एवं जैविक दशा भी परिवर्तित हो जाती है।
- रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा प्रदूषण: रेडियो धर्मी पदार्थ कई प्रकार से मिट्टी में विद्यमान रहते हैं जो जीवों के अलावा मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- मृत पशुओं से प्रदूषण: मृत पशुओं को खुला छोड़ने से जीवाणुओं की क्रियाओं से मांस सड़ने लगता है जिससे मिट्टी में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
- घरों का कचड़ा खेतों में फेंकने से प्रदूषण: किसान भाई बिना गह्वे में सड़ाये घर का कचड़ा खेतों में डाल देते हैं जो जीव और पौधों को हानि पहुंचाते हैं। और मिट्टी की प्रदूषित हो जाती है जिसमें कीड़े आदि मिट्टी में उपलब्ध हो जाते हैं।
- कारखानों के निकली गैसों द्वारा प्रदूषण: कारखानों के निकली गैसों एवं धुएँ में सल्फर एवं नाइट्रोजन के आक्साइड वायुमण्डल से नमी से क्रिया करके गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा जल या नम धुंध से भूमि पर गिरते हैं और मृदा की अम्लीयता को बढ़ाते हैं।

रसायनिक उर्वरकों द्वारा प्रदूषण

मिट्टी में रसायनिक उर्वरकों द्वारा तब प्रदूषण अधिक होता है जब बिना मिट्टी जांच कराये

- असंतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि बुवाई करते समय नमी की कमी होने पर पौधों को जला देनी है। साथ ही मिट्टी की भौतिक रसायनिक दशा बदल देती है अम्लीयता क्षारीयता को बढ़ा देती है।
- जल भराव के कारण प्रदूषण: अधिक जल भराव की स्थिति में मिट्टी लवणीय हो जाती है जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियाँ रुक जाती हैं और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है।
- उत्खनन एवं भवन निर्माण कार्यों से प्रदूषण: खनिजों के उत्खनन एवं भवन निर्माण कार्यों से प्रदूषण ऊपरी सतह पर खदानों से बहकर हानि कारक पदार्थ जमा हो जाते हैं या निर्माण के समय बचे हुए पदार्थ बह कर मिट्टी सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है।
- वनों की अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण: वनों के पेड़ों की कटाई से मिट्टी क्षरण बढ़ता है साथ ही वर्षा भी कम होती है जिससे मिट्टी की उर्वराशक्ति क्षीण होती है।

देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण

पोषण के लिये आवश्यक हो गया है कि हमारे देश की उपलब्ध मिट्टी को सुरक्षित कैसे किया जाये क्योंकि खेती योग्य जमीन लगातार भवन निर्माण आदि में उपयोग होकर घटती जा रही है तथा कुछ क्षेत्र अम्लीयता क्षारीय के कारण खेती के अयोग्य होता जा रहा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज विचार आवश्यक है अन्यथा बहुत देर हो गई होगी जब हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता खो देगा इसलिये आज मिट्टी प्रदूषण का नियंत्रण नहीं प्रबंधन जरूरी है जो हर देशवासी का मानवीय कर्तव्य है।

मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए प्रबंधन



- एकीकृत पौध संरक्षण अपनाते हुए कीट नियंत्रण करें जब तक आवश्यक न हो तब तक कीट रसायन उपयोग न करें और यदि करना आवश्यक हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुसंधित मात्रा को उचित विधि से उपयोग करें।
- रासायनिक खादों का उपयोग मिट्टी की जांच उपरोक्त आवश्यक मात्रा को उचित विधि व समय पर दें।
- खरपतवार प्रबंधन में जहाँ तक संभव हो यांत्रिक विधियों का उपयोग करें यदि रसायन उपयोग करना हो तो उचित सहाय के बाद ही उपयोग करें।
- कारखानों से निकालित पदार्थ जल को वैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचारित कर शुद्ध करके ही खेतों में दें।
- कारखानों से निकालित गैसों की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाये और उसके ऊपर वायु शोधन यंत्र भी होना आवश्यक है।
- अधिक वर्षा एवं पर्यावरण शुद्धिकरण हेतु वनों की कटाई न करें बल्कि खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगावें।
- खेतों की मेड़ बंदी करें, खेतों को समतल करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करें जिससे मिट्टी कटाव न हो।
- घरों से निकलने वाले कचड़े का कम्पोस्ट बनाकर खेतों में डालें।
- मूल-मूत्र एवं गंदे पानी को खेतों में सीधा न जाने दें।
- भवन एवं सड़क निर्माण से बचे हुए कचड़े को खेतों में न डालें तथा खदानों के प्रदूषित पानी को खेत में न आने दें।
- यदि खेतों में वायु प्रदूषण के कारण अम्लीयता बढ़ रही है तो मृदा में चूना का उपयोग करें। साथ ही अम्लीयता सहन करने वाली फसलों की बुवाई करें।
- यदि खेतों की क्षारीयता बढ़ रही हो तो जिप्सम उपयोग के साथ-साथ जैविक खादों का उपयोग बढ़ावें।

मूंगा का भभूतिया रोग



यह रोग दुनिया भर में पाया जाता है, जहाँ मूंग की खेती होती है, मध्यप्रदेश में मूंग का क्षेत्रफल 84 हजार हेक्टेयर एवं उत्पादन 28 हजार टन है। भारत में यह रोग सन 1918 में रिपोर्ट किया गया था। मूंग पर इस रोग का आक्रमण फलियों के बनते समय आसमान में बादल छाये हो तब अधिक होता है। शीघ्र पकने वाली जातियों में हानि कम होती है। परंतु रोग का जब भीषण प्रकोप होता है तब खेत में फलियों की संख्या 20 से 30 प्रतिशत तक घट जाती है और उपज में 40 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है। इस रोग को उत्पन्न करने वाला कवक इरीसाइफ़ी पीसी संसार के विभिन्न भागों में 300 से अधिक परपौषी जातियों पर पाया जाता है और इस कवक के विभिन्न क्रियात्मक प्रभेद कुछ अन्य फसलों जैसे-धनिया, सौंफ, रिजका, उड़द, मटर, गोभी इत्यादि पर भी सक्रमण करते हैं।

अवस्था में ही जीवित बना रहता है। वैसे इसके क्लोरोसिसियम भूमि में गिरे पौधों के रोगग्रस्त अवशेषों पर बनते हैं और यह इन्हीं के द्वारा एक मौसम से दूसरे मौसम में जीवित बना रहता है। अगले मौसम में क्लोरोसिसियम भूमि के समीप वाली पतियों पर सबसे पहले सक्रमण करते हैं। रोग का द्वितीयक सक्रमण, प्राथमिक सक्रमण से बने कवकजाल द्वारा उपजत कोनिडियोम से होता है कोनिडियोम का फलवा (प्रकीर्णन) वायु द्वारा होता है एवं मूंग के बीजों में उपस्थित प्रसुप्त कवकजाल के द्वारा होता है। रोग नियंत्रण: सफाई: भूमि में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को एकत्र करके सुरक्षित स्थान पर जला देना चाहिए।

भभूतिया निरोधक जातियाँ

पूसा बोल्ल, नरेन्द्र मूंग -1, पीडीएम-139 (सम्राट), एमएल-515, के-85 1.25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण को भुरकना चाहिए। किसी घुलनशील गंधक कवकनाशी जैसे: थायोविट, इलोसाल, सल्फेक्स, इनसल्फगोल्ड आदि की 3 किलो ग्राम मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 या 3 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के प्रारंभ होते ही तथा दूसरा व तीसरा छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। विटावेक्स 0.1 प्रतिशत (1 ग्राम प्रति लीटर जल) का छिड़काव करके भी इस रोग को रोका जा सकता है।

लक्षण

सर्वप्रथम रोग पौधों की पतियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधों के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है। प्रारंभ में पतियों की दोनों सतहों पर सफेद चूर्णी धब्बे बनते हैं जो बाद में फली एवं तने इत्यादि के ऊपर भी बन जाते हैं। पहले धब्बे छोटी-छोटी रंगहीन चित्तियों के रूप में बनते हैं परंतु अंत में इनके चारों ओर चूर्णी समूह फैल जाता है। इस प्रकार से रोगी पौधे छोटे रह जाते हैं उन पर फलियाँ भी कम लगती हैं तथा दाने हल्के होते हैं। पतियों के जिस स्थान पर परजीवी का कवक जाल फैला रहता है वहाँ की कोशिकाएँ ऊतकक्षय के कारण मर जाती हैं सक्रमित पतियाँ पीली पड़ कर मूड़ जाती हैं और अंत में गिर जाती हैं। रोग का अधिक प्रकोप होने पर पौधा मर जाता है। कवक इरीसाइफ़ी पीसी अनेक वर्षीय एवं बहुवर्षीय परपौषी पौधों पर आक्रमण करता है। पूरे वर्ष अपनी कोनिडियोमी



बाइंडन का छह महीने तक प्रतिदिन 10 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने का आदेश

सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि पेट्रोल-डीजल के दामों में गिरावट आएगी। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पेट्रोलियम रिजर्व से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल रिलीज करने की बात कही है। गौरतलब है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी तेजी आई है। ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।



अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रणनीतिक भंडार से छह महीने तक प्रतिदिन 10 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने का आदेश दिया है। क्लाइंट हाउस ने बृहस्पतिवार कहा कि यूक्रेन में सैन्य आक्रमण के कारण रूस पर अमेरिका समेत कई देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।

कीमतों में कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। बाइडन ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लिए अपने प्रशासन की योजनाओं पर टिप्पणी करते हुए इस संबंध में यह घोषणा की है। क्लाइंट हाउस के अनुसार, बाइडन अमेरिकी संसद से उन तेल और गैस कंपनियों पर वित्तीय दंड लगाने का

भारत में बढ़े पेट्रोल के दाम

भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों का लगातार बढ़ना जारी है। गुरुवार को भी इनके दामों में प्रति लीटर 84 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। बीते कुछ दिनों से देश में इनकी कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अभी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 93.07 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93.07 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं, मुंबई में पेट्रोल-डीजल के रेट्स में 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर पेट्रोल 116.72 रुपये में पहुंच गया है, जबकि डीजल 100.94 रुपए का हो गया है।

भी आह्वान करेंगे जो सार्वजनिक भूमि पट्टे पर देती हैं लेकिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रही हैं। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिका में महंगाई को 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडन की सरकार के सामने इससे निपटाना एक बड़ी चुनौती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही, जबकि साल भर पहले ये करीब 60 डॉलर प्रति बैरल थीं।

रूस का सस्ते तेल का ऑफर तो अमेरिका ने दी चेतावनी

रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते प्रतिबंधों से बेहाल रूस ने जहां भारत को सस्ती कीमतों पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया, वहीं अमेरिका ने तत्काल इसमें टांग अड़ा दी। दरअसल, रूस ने भारत से कहा है कि वह युद्ध के पूर्व कच्चे तेल की जो भी कीमत थी, उसमें भी 35 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट पर कुल देगा। भारत ने भी इस ऑफर पर हार्थोहाथ लाकना चाहा, लेकिन बीच में अमेरिका ने अपना दांव खेल दिया। वॉशिंगटन के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि अगर भारत तय सीमा से ज्यादा तेल रूस से खरीदता है तो नई दिल्ली मुश्किल में आ सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हमने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वे किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकते। हालांकि, यह एक सीमा तक है और उससे ज्यादा खरीद करने पर परेशानी हो सकती है। भारत अगर रूस या डॉलर में रूस को भुगतान करता है तो इससे अमेरिका को कोई समस्या नहीं है। हमें रूस और भारत के बीच होने वाले सौदे की जानकारी है और हम चाहते हैं कि भारत प्रतिबंधों के दायरे में रहकर ही कोई कदम उठाए। इसका उल्लंघन करने पर नई दिल्ली को मुश्किल हो सकती है।

4500 करोड़ रुपए जुटाएगी वोडाफोन आइडिया

नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने करीब 4500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 338.3 करोड़ शेयर तीन प्रवर्तक समूह की इकाइयों यूरो पैसिफिक सिक्वोरिटीज, प्राइम मेटल्स और ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स को आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इन इकाइयों को ये शेयर 13.30 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आवंटित किए जाएंगे। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। दूरसंचार कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में 14500 करोड़ रुपए का कोष जुटाने की घोषणा की थी। इस राशि में से 4500 करोड़ रुपए प्रवर्तक खालेंगे। वोडाफोन

आइडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, निदेशक मंडल की पुंजी जुटाने से जुड़ी समिति की बैठक में प्रस्ताव पर तैयारी किया गया और नकदी के लिये 10-10 रुपए के भाव वाले 3383458645 इक्विटी शेयर 13.30 रुपए प्रति शेयर यानी प्रति शेयर 3.30 रुपए अधिक के हिस्सा से आवंटित करने की मंजूरी दी गयी। कर्ज में डूबी कंपनी ने सूचित किया था कि उसके निदेशक मंडल ने 14500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इसमें 4500 करोड़ रुपये प्रवर्तक इकाइयों वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह से जुटाना शामिल है।

एयर एशिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय संभव

नई दिल्ली। टाटा समूह सस्ती उड़ानों के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है और इसके तहत समूह की एयरलाइन एयर एशिया इंडिया को हाल में अधिग्रहित एयर इंडिया एक्सप्रेस में मिलाया जा सकता है।



एयरलाइन उद्योग के सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही एयर इंडिया की क्षमता का एक हिस्सा सस्ती उड़ानों के क्षेत्र में लगाने की भी योजना है। सूत्रों के अनुसार मौटे तौर पर रणनीति यह है कि एयर इंडिया की पूर्ण-सुविधा वाली उड़ानें दिल्ली-मुंबई और चेन्नई-मुंबई जैसे प्रमुख किागों पर रखी जाएं तथा अन्य मार्गों पर समूह की विमान सेवा उड़ानें परिचालित की जाएं। सस्ती उड़ानों के बाजार में समूह की सक्रियता बढ़ने से

इंडिगो और स्प्राइजेट जैसी बजट-उड़ान सेवा कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में एयर एशिया इंडिया के पूर्ण विलय में अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन टाटा समूह के तहत एयर इंडिया के नए प्रबंध-तंत्र ने सिद्धांत के तौर पर यह यत्न कर लिया है कि पूर्ण सुविधा वाली उड़ान सेवाएं प्रमुख मार्गों तक ही सीमित रखी जाएंगी। उनका कहना है कि

एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अपनी सेवाओं को मजबूत करने का अभियान जारी रखेगी। इस संदर्भ में टाटा समूह को भेजे गए सवाल पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है।

टाटा समूह एयर इंडिया और उसकी अनुपंगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदने के बाद इस एयरलाइन को घाटे से उभारने की रणनीति पर काम कर रही है। उड्डयन उद्योग के एक विश्लेषक ने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयर एशिया इंडिया का विलय और घरेलू मार्गों पर सस्ती उड़ानों में बढ़ोतरी करने का समूह का फसला एक तार्किक कदम हो सकता है। घरेलू बाजार में टाटा समूह की सभी एयरलाइनों में हिस्सेदारी में तेजी दिखी है। बाजार में जनवरी के मुकाबले हिस्सेदारी फरवरी में बढ़कर 10.2 प्रतिशत से 11.1 प्रतिशत हो गयी है।

सस्ती उड़ानों में हिस्सा बढ़ाने की तैयारी में टाटा समूह

बीते सालों में सस्ती उड़ानों की ओर ग्राहकों का झुकाव बढ़ा

बीते कुछ सालों में सस्ती उड़ानों की तरफ ग्राहकों का झुकाव बढ़ने के मद्देनजर देश में सस्ती उड़ानों के बाजार में बड़ी तेजी से विस्तार दिखा है। टाटा समूह की एयर लाइन विस्तार और एयर इंडिया पूर्ण सुविधा वाली एयर लाइन है। घरेलू विमान यात्रा बाजार में उनका समिलित हिस्सा 21 प्रतिशत है। बाकी के बाजार में सस्ती सेवाएं देने वाली इंडिगो, स्प्राइजेट और गो फ्लर्ट बाजार में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। एयरलाइन कंपनियों मुख्य तौर पर यात्रियों को उड़ान के दौरान मनोरंजन और पसंद के खान-पान सुविधा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।

फरवरी में सलाना आधार पर 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

गयी। इन क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों में उत्पादन क्रमशः 22.4 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत ऊंचा रहा। कच्चे तेल के उत्पादन में इस वर्ष फरवरी में एक साल पहले इसी माह की तुलना में 2.2 प्रतिशत गिरावट रही। जबकि अप्रैल-फरवरी में कच्चे तेल का उत्पादन इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि से 2.6 प्रतिशत कम रहा। उर्वरक उत्पादन में भी फरवरी में 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी, जबकि इस दौरान वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में इसके संयोज उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की कमी आयी है। दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक के आंकड़े अभी प्रारंभिक अनुमान पर आधारित हैं।

बुनियादी उद्योगों का उत्पादन बढ़ा

नई दिल्ली। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात जैसे क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ने से आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में फरवरी 2022 में सलाना आधार पर 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, फरवरी में आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन सूचकांक 5.8 प्रतिशत बढ़कर 137.1 अंक रहा। फरवरी में कोयले का उत्पादन फरवरी 2021 की तुलना में 6.6 प्रतिशत बढ़ा। चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों अप्रैल-फरवरी 2021-22 में कोयला का उत्पादन इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 9.8 प्रतिशत बढ़ा है। प्राकृतिक गैस के

उत्पादन में फरवरी माह के दौरान 12.5 प्रतिशत दर्ज की गयी। जबकि चालू वर्ष के 11 महीनों में इस क्षेत्र का उत्पादन एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 20.5 प्रतिशत बढ़ा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग का उत्पादन फरवरी में 8.8 प्रतिशत ऊंचा रहा। जबकि चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में इस क्षेत्र के उत्पादन में 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है। इस्पात उत्पादन में 5.7 प्रतिशत इजाफा : इस्पात उत्पादन फरवरी में 5.7 प्रतिशत तथा अप्रैल-फरवरी 2022 में 18.4 प्रतिशत बढ़ा है। फरवरी में सीमेंट और विद्युत के उत्पादन में भी क्रमशः 5.0 और 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

वित्तीय घाटा 13 लाख 20 हजार करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी 2022 तक देश का वित्तीय घाटा 13 लाख 20 हजार करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कुल प्राप्ति 1827280 करोड़ रुपए और कुल व्यय 3143875 करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में कुल व्यय पुनर्निर्मित बजट अनुमान का 83/4 प्रतिशत और कुल प्राप्ति 83/9 प्रतिशत रही है। सरकार की कुल प्राप्ति में कर राजस्व 1480886 करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व 310131 करोड़ रुपए रहा है। ऋण वसूली 22749 करोड़ रुपए और विविध पुंजीगत प्राप्ति 13514 करोड़ रुपए रही है। इस अवधि में राज्यों को 787822 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गये हैं। सरकार के व्यय में 2658694 करोड़ रुपए राजस्व खाते से और 485181 करोड़ रुपए पूंजीगत खाते से हुये हैं। कुल राजस्व व्यय में 670501 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर कुंयो गये हैं जबकि 382161 करोड़ रुपए के भुगतान सखिडी के तौर पर किये गये हैं।

बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक

मुंबई। वैश्विक तर से मिले नाकरात्मक संकेतों के साथ ही घरेलू स्तर पर हेथकेयर, आईटी, टेक, वित्त, एनर्जी और बेसिक मटेरियल्स जैसे समूहों में हुई बिकवाली के कारण शेयर बाजार में जारी तेजी पर ब्रेक लग गया और इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 0.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 115.48 अंक टूटकर 58568.50 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का निफ्टी 33.50 प्रतिशत गिरकर 17464.75 अंक पर रहा। बीएसई में दिग्गज कंपनियों में जहां

बिकवाली हुई वहीं छोटी और मझौली कंपनियों में लिवाली का जोर रहा जिससे बीएसई का मिडकैप 0.29 प्रतिशत बढ़कर 24107.97 अंक पर और स्मॉलकैप 0.31 प्रतिशत उठकर 28215.65 अंक पर रहा। वैश्विक स्तर पर लगभग सभी प्रमुख सूचकांक गिरावट में रहे।

इसमें हांगकांग का हैंगसेंग 1.06 प्रतिशत, जापान का निक्केई 0.73 प्रतिशत, जर्मनी का डैक्स 0.35 प्रतिशत, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.44 प्रतिशत और ब्रिटेन का एफटीएसई 0.23 प्रतिशत शामिल है।

बाजार समीक्षा वैश्विक दाम ऊंचे होने से चीनी की निर्यात मांग जोरदार शकर कोटा 22 लाख टन, तेजी की धारणा

इंदौर। केंद्र सरकार ने अप्रैल की खपत के लिए चीनी मिलों को 22 लाख टन मासिक बिक्री कोटा जारी किया है, जो मार्च की तुलना में 50 हजार टन अधिक है, लेकिन पिछले साल अप्रैल 2021 की तुलना में समान है। जानकारों का मानना है कि आगामी दिनों गर्मी के सीजन की खपत बढ़ने को देखते हुए शकर में तेजी की धारणा है। वैश्वे भी पिछले दो साल कोराना की वजह से शकर के उठाव में कमी हुई थी, जबकि इस वर्ष अभी स्थिति बेहतर होने से शीतलपेय पदार्थ, आइस्क्रीम, श्रूडिड आदि के साथ शादी-ब्याह में मेहमानों की संख्या में इजाफा होने से शकर की खपत अधिक रहेगी।



निर्यात हो चुका है। आगामी दिनों निर्यात और बढ़ने का अनुमान है, लेकिन सरकार घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण के लिए संभवतः 80 लाख टन निर्यात अनुबंध होने के बाद इस पर रोक लगा सकती है। देश में इस साल 333 लाख टन शकर का रिजर्व उत्पादन होने की संभावना है। सरकार ने गत मार्च माह में 21.50 लाख टन शकर का कोटा जारी किया था। अभी मार्च एंडिंग की वजह से मांग सीमित है, जो एक अप्रैल बाद तेजी से बढ़ सकती है।

खाद्य तेल-तिलहन पर स्टॉक सीमा अवधि दिसंबर तक बढ़ी

इंदौर। सरकार ने खाद्य तेल व तिलहन पर लागू स्टॉक लिमिट अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दी है। मार्च के दौरान मलेशिया का पाम तेल निर्यात 6.68 फीसदी बढ़कर 12.92 लाख टन हुआ। देश के 5 बड़े बंदरगाहों के खाद्य तेलों का स्टॉक 21 मार्च के 6.25 लाख के मुकाबले 28 मार्च को 2.78 लाख टन रह गया। देश में सरसों आवक मात्र 3.50 लाख बोरी हुई। जयपुर में तेल कंडीशन वाली सरसों 7175-7200 पर मजबूत थी। मलेशिया पामतेल वायदा 1680 डॉलर था। केएलसीई 214 रिगिट नीची बंद हुआ। शिकागो सोया तेल वायदा रनिंग में 101 सेंट नीचा था। खाद्य तेल प्रति 10 किलो के सौदों में सोया रिफाईड 1495-1500, सॉल्वेंट 1465-1470, मुंबई 1470, मूंगफली तेल 1600-1620, मुंबई 1620, गुजरात 1575, पामतेल मुंबई 1440, इंदौर 1535, कॉटन तेल 1510 रु था। प्लांट सोयाबीन प्रेस्ट्रीज 7700, अंबिका 7850, धानुका 7825, एमएस नीम 7850, रुचि 7750, अवि 7700, महाकाली 7800 रु था। **कपास खादी घटक** प्रति 60 किलो इंदौर, देवास-उज्जैन 2300 -2305, खडवा बुरहानपुर 2275, अकोला 3400 रु थी।

कमजोर मांग से कच्चा तेल वायदा में गिरावट

नयी दिल्ली। हाज़िर बाजार में कमजोर मांग का असर गुरुवार को कच्चा तेल वायदा में गिरावट के रूप में दिखा दरअसल, वायदा कारोबारियों द्वारा सौदों का आकार कम करने से कच्चे तेल की कीमत 4.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज में कच्चे तेल के अर्धल डलीवरी अनुबंध की कीमत 342 रुपये की गिरावट के साथ 7773 रुपये प्रति बैरल रह गई। इसमें 5161 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर वेस्ट टेदास इंटरमीडिएट कच्चा तेल 4.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 103.21 डॉलर प्रति बैरल रह गया। वहीं न्यूयॉर्क में ब्रेट कच्चा तेल 3.99 प्रतिशत की गिरावट के साथ 108.92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

महाराष्ट्र मिलों द्वारा किसानों को 96 प्रतिशत गन्ने का भुगतान

मुंबई। महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने किसानों 25931.09 करोड़ रु उचित और लाभकारी मूल्य चुकाया है, जो 2021-22 सीजन के लिए कुल गन्ने का लगभग 96 प्रतिशत है। 15 मार्च 2022 तक कुल देय 27075.33 करोड़ रुपए है। जिसके लिए 194 मिलों द्वारा 944.24 लाख टन गन्ना पैदाई की गई है। प्रदेश की लगभग 76 मिलों ने 100 प्रतिशत भुगतान किया है, जबकि 59 मिलों ने 80 से 99 प्रतिशत के बीच का भुगतान किया है। 118 मिलों के कारण 948.77 करोड़ रुपए आरपी बकाया है, जबकि पिछले वर्ष की एफआरपी बकाया राशि 478.57 करोड़ है। महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त कार्यालय ने एफआरपी भुगतान करने में विफल चीनी मिलों के

खिलाफ अभी तक राजस्व और वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) आदेश जारी नहीं किया है। 30 मार्च तक राज्य में चीनी मिलों ने 1131.91 लाख मीट्रिक टन गन्ना पैदाई के साथ 117.60 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के चीनी वेल्ड में क्रशिंग अगले महीने के अंत तक जारी रहेगी। इस बीच, वेस्ट इंडियन शुगर लिमिटेड एग्रीकल्चर ने सरकार से अतिरिक्त गन्ना को परिवहन और चीनी रिकवरी में गिरावट के लिए राज्य सरकार से अनुदान की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इस साल महाराष्ट्र ने चीनी उत्पादन के मामले में यूपी को पीछे छोड़ते हुए अक्विल स्थान पाया का गौरव एक बार फिर अर्जित कर लिया है। यूपी में इस बड़ा उत्पादन गत वर्ष से कम रहा है।

सोना व चांदी की कीमतों में मजबूती का माहौल

इंदौर। गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी था। वैश्विक मजबूती के बीच कॉमेक्स पर सोना ऊंचे में 1940.3, नीचे में 1918.8 के बाद 1938.9 डॉलर पर प्रति औंस 5 डॉलर ऊंचा चल रहा था। वहीं भी चांदी ऊंचे में 2510, नीचे में 2450 के बाद 2509 डॉलर प्रति औंस पर 11 सेंट ऊंची चल रही थी। **इंदौर सराफा**- सोना केश में टंच 52200, कैडबरी 52100, आरटीजीएस 52650 रु प्रति 10 ग्राम, चांदी केश में टंच 67500 वीरसा 67400, आरटीजीएस में 68500 रु प्रति किलो थी। **रतलाम**- आरटीजीएस सोना 53150 एवं चांदी 68200 रु थी। **उज्जैन**- सोना 52300, चांदी प्रति किलो 67800 रु थी।

वैश्विक सराफा विवरण	सोना	चांदी
ऊंचे में	1940.30	25.10
नीचे में	1918.80	24.50
रनिंग में	1938.90	25.09

बादाम 15 दिन में 100 रु किलो उछली

इंदौर। बादाम की कीमतों में जारी तेजी का रख गुरुवार को भी जारी रहा। इसके चलते विगत 15 दिन में इसके दाम करीब 100 रु किलो बढ़ गए हैं। दरअसल वर्तमान में कमजोर आपूर्ति के बीच वैवाहिक सीजन की मांग बढ़ने के साथ ही स्टॉक-रिजर्व के सक्रिय होने से तेजी को बल मिल रहा है। शकर का अप्रैल माह का मासिक कोटा 22 लाख टन जारी हुआ है। नारियल की जोरदार मांगों बीच कीमतों में मजबूती रही। कालीमिर्च में फिर नए सिरे से 4 रु किलो की तेजी रही। जीरा स्थिर था। शकर 3480-3500, सुपर 3520-3540, एम 3650-3675, यूप 2850-4000, कालीमिर्च कालामोती 538, दीपक 552, गणेश 572, मटरदाना 586, जीरा पंजा 243 खुशबू 245 सुपर 250-260, हल्दी सांगली 165-166, निजामाबाद 110-130, नारियल प्रति बोरी 120 भर्ती 1750-1800, 160 भर्ती 1850-1900, 200 भर्ती 2050-2100, 250 भर्ती 2250-2300, खोपरा गोला 195-215, खोपराबूरा 15 किलो 2400-4400, साबूदाना 4350-4700, बरलसभी 5050, रत्नास 5550, बरलसभी 1 किलो पैक 5750, सोंफ 150-210, हल्की 121-135, लौंग 675-750, दालचीनी 285-295, जायफल 750-850, जावत्री 1950-2100, बड़ी इलायची 725-850,



तरबूज मगज 310-340, चारोली 1050-1250, इलायची एक्सटा बोर्ड 1800-1850, बोर्ड 1650-1700 मध्यम 1550-1600, मिनी 1400-1500, पानपट्टी 1300-1400, पोस्ता 1500-1750, काजू (240) 770-790, (320) 690-705, डब्ल्यू वन (300) 670-680, एस एस डब्ल्यू 630-650, जेएफ 620-630, टुकड़ी 600-650, बादाम इन्डिपेंडेंट 625-640, अमेरिकी 660-670, आस्ट्रेलियन 675, टॉच 525-530, किशमिश 375-550, इंडियन 180-230, मखाना 450-800, पिसता 1450-1575, नमकीन 870-950 रु। आटा-मैदा (50 किलो) आटा 1350-1370, मैदा 1400-1410, बालू 1440-1450, बेसन 3325-3350 रु।

बांग्लादेश की सरकार भारत से कर सकती है चीनी का आयात

ढाका। भारत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (जी-2-जी) अरेंजमेंट के तहत बांग्लादेश को चीनी निर्यात करने का विचार कर रही है। राष्ट्रीय सखरीय उपभोक्ता फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) के प्रबंध निदेशक मनोज सेमवाल ने 23 मार्च को जारी पत्र में बांग्लादेश सरकार को अनुरोध किया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इस पत्र के अनुसार बांग्लादेश का वाणिज्य मंत्रालय रमजान के आने वाले महीने में सखिडी पर चीनी, मसूर और खाद्य तेल मुहैया कराने वाला है। एनसीसीएफ जी 2 जी आपूर्ति अनुबंध के तहत बांग्लादेश को चीनी निर्यात करने के इच्छुक है। पत्र में यह भी बताया गया है कि, एनसीसीएफ ने पिछले जी-2- जी आपूर्ति अनुबंध के तहत वर्ष

2020-21 में बांग्लादेश के खाद्य निदेशालय के लिए भारतीय गैर-बासमती चावल को सफलतापूर्वक आपूर्ति की थी। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए कहा हमें हाल ही में पत्र मिला है। हम इस पर काम कर रहे हैं। एनसीसीएफ के पास बांग्लादेश के लिए गेहूँ और गैर-बासमती चावल सहित खाद्य अनाज के खरीद, हैडलिंग व निर्यात में विशाल अनुभव है। बांग्लादेश को रमजान के दौरान, 0.3 मिलियन टन चीनी की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के मुताबिक औसतन, प्रति माह 0.11 मिलियन टन चीनी की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, सरकार बांग्लादेश (टीसीबी) के राज्य संचालित व्यापार निगम द्वारा चीनी की बिक्री करती है।

एफआईएच प्रो लीग: इंग्लैंड पर जीत दर्ज कर शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा भारत



भुवनेश्वर ।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम एफआईएच प्रो लीग में आठ मैचों के बाद अच्छी स्थिति में है और इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू हो रहे दो मैचों में जीत दर्ज करके वह तालिका में शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा। इस मुकाबले का दूसरा मैच रविवार को खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत ने अब तक इस सत्र में आठ मैच खेले हैं और वह 16 अंकों के साथ जर्मनी (17 अंक) के बाद तालिका में दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने फ्रांस (5-0, 2-5) और स्पेन (5-4, 3-5) के खिलाफ एक मैच में जीत दर्ज की थी जबकि एक मैच में उसे हार मिली थी। इससे पहले उसने दक्षिण अफ्रीका को 10-2, 10-2 से हराया था। भारत को हाल में अर्जेंटीना के खिलाफ पहले मैच में 2-2 (शूट-आउट में 1-3) से हार का सामना करना पड़ा लेकिन दूसरे मैच में उसने 4-3 से

रोमांचक जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले रक्षापंक्ति भारत के लिये चिंता का विषय है, जो दबाव में बिखर जाती है। भारत ने कुछ गोल आसानी से गंवाये हैं और उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने आक्रामक किया है कि टीम को अपने रक्षण में सुधार करना होगा। हरमनप्रीत ने कहा, 'हमारा मुख्य ध्यान टीम को मैच दर मैच मजबूत बनाना है। हम अपने कमजोर और मजबूत पक्षों के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें अपनी 'फिनिशिंग' में सुधार करने, अधिक पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने की जरूरत है। रक्षकों को पेनल्टी कॉर्नर देने से बचना होगा। भारत की अग्रिम पंक्ति ने हालांकि प्रभावशाली प्रदर्शन करके आठ मैचों में 42 गोल किये हैं। मदीप सिंह विशेष रूप से विपक्षी टीम के सर्कल के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण गोल किये हैं जिनमें अर्जेंटीना के खिलाफ आखिरी मिन्ट में किया गया विजयी गोल भी शामिल है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की अनुवाद वाली मध्यपंक्ति में हार्दिक सिंह, विवेक स्मर प्रसाद, नीलकांठ शर्मा और सुमित जैसे खिलाड़ी हैं। टीम में

चार विश्व स्तरीय ड्रैग फिलकर हरमनप्रीत, कप्तान अमित रोहिदास, वरुण कुमार और युवा जुगराज सिंह हैं जिससे भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों पर मजबूत नजर आता है। जुगराज ने सीनियर टीम में पदार्पण करने के बाद से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ दूसरे मैच में दो गोल किये थे। रोहिदास ने कहा, 'वह (जुगराज) वास्तव में अच्छा खेल रहा है। वह विश्व स्तरीय ड्रैगफिलकर है। यह टीम के लिए फायदे की स्थिति है। वह मौकों का पूरा लाभ उठा रहा है। भारत ने

बाबर आजम ने तोड़ा इमरान खान का 32 साल पुराना रिकॉर्ड

लाहौर । पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने यहां गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पूर्व क्रिकेटर एवं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पूर्व क्रिकेटर एवं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाहौर के गढ़ाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बाबर ने 83 गेंदों पर 114 रन की शतकीय पारी खेल कर 32 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के किसी भी कप्तान द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया यह सर्वाधिक वनडे स्कोर है। इससे पहले इमरान खान ने बतौर कप्तान 1990 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन बनाए थे। उसके बाद से अब बाबर ने बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक वनडे स्कोर बनाया है। उल्लेखनीय है कि बाबर और इमाम-उल-हक के शानदार शतकों के दम पर पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हरा कर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।



संक्षिप्त समाचार

इन गेंदबाजों की टीम में रहना राजस्थान रॉयल्स के लिए मनोबल बढ़ाने वाला : संगकारा

मुंबई । राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक और मुख्य कोच कुमार संगकारा ने शुक्रवार को कहा कि सभी गेंदबाजों का उपलब्ध रहना टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है जबकि आईपीएल की कई अन्य टीम अपने विदेशी खिलाड़ियों की फिटनेस और अनुपलब्धता से जूझ रही हैं। रॉयल्स ने टेंट बोल्ड, प्रसिद्ध कृष्णा, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल की मौजूदगी वाले दमदार आक्रमण के शानदार प्रदर्शन से अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से करारी शिकस्त देकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। कई टीम के विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हैं जबकि रॉयल्स के चार मुख्य गेंदबाजों के अलावा जिम्मी नीशाम, ओबेद मैककार्य और नवदीप सेनो भी पूरे सत्र के लिए उपलब्ध हैं। संगकारा ने कहा कि टी20 क्रिकेट में विशेषकर सपाट पिचों पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी समान प्रभाव डालती है। इसलिए यह वास्तव में मनोबल बढ़ाने वाला है कि हमारे पास सभी गेंदबाज पूरे सत्र के लिए उपलब्ध हैं। आईपीएल में 122 मैचों में 170 विकेट लेने वाले लक्ष्मि मलिंगा सन्यास लेने के बाद तेज गेंदबाजी कोच के रूप में रॉयल्स से जुड़ गए हैं। संगकारा ने कहा कि यह वास्तव में अच्छा है कि वह टीम के साथ हैं। उनका होना काफी मायने रखता है। गेंदबाज उनसे बात करने का वास्तव में फायदा उठा रहे हैं। वे क्षेत्ररक्षण की सजावट और गेंदों पर चर्चा करते हैं।

महिला विश्वकप फाइनल : इंग्लैंड की स्पिनर एतलेस्टोन ने कहा- हम आस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं

क्राइस्टचर्च । इंग्लैंड की बाई हाथ की स्पिनर सोफी एतलेस्टोन का कहना है कि उनकी टीम अगर अपना सर्वश्रेष्ठ करे तो वह किसी भी दिन मजबूत आस्ट्रेलिया को हरा सकती है जिससे रविवार को हेगले ओवल में उन्हें महिला विश्व कप फाइनल खेलना है। टूर्नामेंट की सर्वाधिक विकेट चटकाने वाली इस गेंदबाज ने साथ ही कहा कि उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेलने के बावजूद फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया को फाइनल में हराना, एशेज में हमारा जैसा प्रदर्शन रहा है, उसके बाद अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं इसे शब्दों में बर्ना नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि यह टीम किसी भी दिन निश्चित रूप से आस्ट्रेलिया को हरा सकती है, हमारे पास एक बढ़िया मौका है। इंग्लैंड का विश्व कप से पहले प्रदर्शन काफी खराब रहा जिसमें टीम एशेज में अपनी पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी से हार गई। इसके बाद विश्व कप के शुरुआती मैच में भी उन्हें आस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलें और हमारे बल्लेबाज वैसी बल्लेबाजी करें जैसा वे कर सकते हैं और गेंदबाज वैसी गेंदबाजी करें जैसी वे कर सकते हैं तो हमारे पास इतनी बढ़िया इकाई है। बल्लेबाजी करें जैसा वे कर सकते हैं और गेंदबाज वैसी गेंदबाजी करें जैसी वे कर सकते हैं तो हमारे पास इतनी बढ़िया इकाई है। इसलिए हम सिर्फ खुद पर ध्यान लगाएँ और अपना सर्वश्रेष्ठ करें।

2022 महिला विश्व कप फाइनल के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा

क्राइस्टचर्च । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को तीन अप्रैल को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले 2022 महिला विश्व कप फाइनल के लिए महिला मैच अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की। भारत की जीएस लक्ष्मी को हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी में पहली महिला सदस्य बनीं थीं। उन्हें भी फाइनल के लिए मैच रेफरी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी ने इस मैदान पर 31 मार्च को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल मैच में भी मैच रेफरी की भूमिका निभाई थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की लॉरेन एगनबर्ग और न्यूजीलैंड की किम कॉटन को ऑन-फील्ड अंपायर बनाया गया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2020 के फाइनल में कॉटन एकमात्र महिला मैच अधिकारी थीं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की जैकलीन विलियम्स, जो 2020 में पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में तीसरे अंपायर के रूप में अंपायरिंग करने वाली अंतरराष्ट्रीय मैच में तीसरे अंपायर के रूप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनीं थीं, टीवी अंपायर के रूप में कार्यभार संभालेंगी, जबकि जिम्बाब्वे की लैंगटन रुसेरे चौथी अंपायर होंगी।

नाकामुरा और रिचर्ड रापोर्ट नई फीडे कैडिडेट्स शतरंज में जगह



बर्लिन, जर्मनी ।

यूएसए के हिकारू नाकामुरा और हंगरी के रिचर्ड रापोर्ट आधिकारिक तौर पर अब फीडे कैडिडेट्स 2022 का हिस्सा होंगे और वह अब पहले से चयनित छह खिलाड़ियों के साथ विश्व चैंपियनशिप में पहुंचने की कोशिश करेंगे। दरअसल शतरंज में विश्व चैंपियन को चुनौती फीडे कैडिडेट का विजेता देता है और अलग अलग चयन के मापदंडों से अब तक विश्व चैंपियनशिप चैंलेंजर रूस के इवान नेपोमिन्सी, विश्व कप के प्रथम दो - पोलैंड के यान डूझा पिछले विश्व कप विजेता अजरबैजान के तैमूर रदजाबोव और रूस के सेरगी कार्याकिन, फीडे ग्रांड स्विस से फ्रांस से अलरीखा फिरोजा और यूएसए के फबियानो करुआना पहले ही इसमें स्थान बना चुके थे। ऐसे में अंतिम दो स्थान का चयन फीडे ग्रांप्री के तीन टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से होना था। ऐसे में हंगरी के रिचर्ड रापोर्ट ने 20 अंक अंक बनाकर सबसे

आगे थे ऐसे में जैसे ही बर्लिन ग्रांप्री के सेमी फाइनल में नाकामुरा पहुंचे यह तय हो गया कि अब वह भी कम से कम 20 अंक हासिल कर लेंगे साथ ही यह भी तय हो गया कि अब कोई अन्य खिलाड़ी इतने अंक हासिल नहीं कर पाएगा। विश्व शतरंज द्वारा आयोजित ग्रांप्री के पूल चरण के अंतिम और निर्णायक दौर में, हिकारू नाकामुरा ने एंड्री एस्पिको को हराया और पूल ए के विजेता बने। फीडे कैडिडेट्स का आयोजन इस वर्ष 16 जून से 5 जुलाई के दौरान स्पेन के मेड्रिड में किया जाएगा जिसमें जीतने वाली खिलाड़ी विश्व चैंपियन मेनानस कार्लसन को चुनौती देगा।

महिला विश्व कप फाइनल में मैच रेफरी होंगी भारत की जीएस लक्ष्मी



क्राइस्टचर्च । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में जगह बनाने वाली पहली महिला भारत की जीएस लक्ष्मी रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले महिला विश्व कप फाइनल में मैच रेफरी होंगी। पुरुष एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाली लक्ष्मी पहली महिला मैच रेफरी हैं। उन्होंने दिसंबर 2020 में यूएई में विश्व कप लीग दो के दौरान यह भूमिका निभाई थी। हेगले ओवल में होने वाले महिला विश्व कप फाइनल के दौरान लक्ष्मी मैदान की भूमिका निभाई थी। जर्मनी की रहने वाली जैकलीन विलियम्स टीवी अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की तीन मैच की घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में यह भूमिका निभाई थी। जिम्बाब्वे के लैंगटन रुसेरे चौथे अंपायर होंगे। आईसीसी ने कहा, 'खेल में लैंगक समानता के प्रति रणनीति प्रतिक्रिया को देखते हुए।

भारत की नजरें जूनियर हॉकी विश्व कप में

3 ओलिम्पियन करवा रहे तैयारी पोटचेपस्टूम ।

कप्तान सलीमा टेटे सहित तीन ओलिम्पिक खिलाड़ियों की मौजूदगी में भारतीय टीम शुक्रवार से यहां शुरू हो रहे एफआईएच महिला जूनियर विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेगी। टेटे के अलावा मिडफील्डर शर्मिला देवी और स्ट्राइकर लालरेमसियामी उस सीनियर टीम में शामिल थे जिन्होंने टोक्यो ओलिम्पिक में चौथा स्थान हासिल किया था। भारतीय

पहली महिला ओलिंपियन है। वह शानदार स्ट्राइकर हैं, जो विरोधी टीम के सर्कल के अंदर तेजी से मौकों के लिए जानी जाती है। अग्रिम पंक्ति की खिलाड़ी शर्मिला ने मैदान के दोनों तरफ से अपने खेल से प्रभावित किया है। उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ भारत के पूल चरण के मैच में भी एक गोल किया। 4 साल में एक बार होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन दिसंबर में होना था लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन (कोरोना वायरस का प्रकार) के खतरे के कारण स्थगित कर दिया गया था। जून आलंपिक 2018 में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही सलीमा ने कहा



खिलाफ एफआईएच हॉकी प्रो लीग मैचों में सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया था। भारतीय टीम ने विश्व कप शुरू होने से पहले इंग्लैंड और नीदरलैंड के खिलाफ भी दो अभ्यास मैच खेले, दोनों ड्रॉ रहे। जूनियर वैश्विक स्पर्धा में भारत ने 4 बार भाग लिया है जहां उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 में कांस्य पदक रहा है। टीम टूर्नामेंट के पिछले सत्र में क्वालीफाई नहीं कर पाई थी।

मैनचेस्टर सिटी के साथ प्रशिक्षण लेंगे यूक्रेनी फुटबॉलर एंड्री क्रावचुक

मैनचेस्टर । यूक्रेनी शरणार्थी एवं फुटबॉलर एंड्री क्रावचुक को प्रीमियर लीग से मंजूरी मिलने के बाद इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के साथ प्रशिक्षण करने की अनुमति दे दी गई है। यह फैसला मैनचेस्टर सिटी और यूक्रेन फुटबॉल टीम के डिफेंडर ओलेक्जेंडर जिनचेंको के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है। युवा स्तर पर क्रावचुक और जिनचेंको दोनों शख्तार डोनेट्स्क में एक साथ खेले हैं। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण शुरू होने के वक्त क्रावचुक अपने रूसी क्लब पक्ष टॉरपीडो मांस्को के साथ तुर्की में प्रशिक्षण शामिल

में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रावचुक ने यूक्रेन पर हमले के बाद तुरंत रूसी क्लब के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया और मैनचेस्टर चले गए, जहां वह मैनचेस्टर सिटी की अंडर-23 टीम के साथ शेष सत्र के लिए प्रशिक्षण लेंगे। क्रावचुक ने रूसी क्लब के लिए खेलने के बारे में कहा, 'मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। मैं ऐसे देश के लिए खेल रहा था, जिसने मेरी मातृभूमि पर आक्रमण किया। क्लब छोड़ना ही एकमात्र फैसला था। अगर मैं वहां खेलना जारी रखता हूँ तो यूक्रेन के लोग मुझे नहीं समझते। उल्लेखनीय है कि 23 वर्षीय क्रावचुक का परिवार अभी भी एलेक्स देश के सशस्त्र बलों के साथ देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। क्रावचुक ने इस बारे में कहा, 'मैं अपने भाई को हर दिन कहता हूँ कि न केवल हमारे परिवार, बल्कि पूरे देश और यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए मुझे उस पर कितना गर्व है। वह वहां रह रहा है और लड़ रहा है। मैं सच में चिंतित हूँ। मैं सोशल मीडिया पर काफी समूहों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार बमबारी अलर्ट के साथ संदेश प्राप्त कर रहा हूँ। हर बार जब भी अलर्ट आते हैं तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। मेरे मन में केवल यही विचार होता है कि मेरे परिवार की जान जा सकती है। क्रावचुक ने कहा कि वह मैनचेस्टर सिटी के आगामी हैं, जिसने उन्हें क्लब में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी। उनके हमवतन जिनचेंको ने भी उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्ते और महीने बहुत मुश्किल रहे हैं, लेकिन मैदान पर वापस आना उनके लिए बहुत मायने रखता है।

अय्यर की कप्तानी को लेकर इरफान पटान का बड़ा बयान

मुंबई । भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पटान ने शुक्रवार को कहा कि दो बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का भविष्य बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में उज्वल है। अय्यर को आईपीएल 2022 से पहले कोलकाता की ओर से कप्तान नियुक्त किया गया था और उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कम स्कोर वाले मैच में तीन विकेट से हार का सामना करने के बावजूद जिस तरह से नेतृत्व किया है, उससे सभी को प्रभावित किया है। पटान ने कहा कि श्रेयस अय्यर एक शानदार कप्तान हैं। याद रखें, उन्होंने सीजन के बीच में (दिल्ली कैपिटल्स) कप्तानी संभाली, जैसे रोहित शर्मा जिन्हें आईपीएल 2013 में सीजन के दौरान मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए श्रेयस ने अच्छी शुरुआत की। कोच रिकी पॉटिंग की देखरेख में उन्होंने कप्तान के रूप में अपने पहले कार्यकाल में अपने निर्णय लेने के कौशल में सुधार किया। पटान ने देखा कि प्रमुखता से सामने आ रही हैं और जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा हम इसके बारे में और बात करेंगे। वह खिलाड़ियों के कप्तान हैं। वह हर मोड़ पर खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं जो एक नेता का अंश संकत है। उनकी देखरेख में कोलकाता का भविष्य उज्वल है और हमने पहले दो मैचों में इसकी झलक देखी है। कोलकाता को उम्मीद होगी कि अय्यर का नेतृत्व शुक्रवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2022 में उन्हें जीत की राह पर ले जाएगा।

केवल बीजेपी ग्राम प्रधान और पार्षदों को विधायक बनाने का दम रखती है : योगी

लखनऊ, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। विधानसभा में हमें भारी बहुमत मिला है। अब विधान परिषद में भी जीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपके बीच आह्वान करने आया हूँ। भाजपा वो दल है जो ग्राम प्रधान से पार्षद तक को विधायक बनाने का दम रखती है। साधारण कार्यकर्ता भी उच्च पद तक जा सकता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव की दृष्टि से प्रदेश भर के महापौर, नगर पालिका के चेयरमैन और ग्राम प्रधान सभी पार्षदों के साथ संवाद कार्यक्रम में कही।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जुड़े 32 हजार से अधिक लोगों से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाकर विधान परिषद में बहुमत दिलाने को कहा। जिससे निर्बाध रूप से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोक कल्याण और गरीबों के कल्याण के लिए तेजी से किया जा सके। सीएम ने वर्चुअली बैठक में जुड़े भाजपा के सभी पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, पार्षदों, ग्राम पंचायत अधिकारियों से कहा कि 9 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव होने हैं। इसलिए अगले 4-5 दिन प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए रणनीति

बनाकर काम करें। ऐसी कार्ययोजना बनाएँ जिससे हरेक सीट पर भाजपा को जीत हासिल हो सके। प्रदेश के अधिकतर ब्लाक प्रमुख भी भाजपा के समर्थक हैं। कई चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन सबका सहयोग लेकर प्रत्याशियों को जिताने का काम करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 36 में से 9 सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त कर चुकी है। 27 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके उच्च सदन के लिए 36 सदस्यों की बड़ी भूमिका होगी। जब प्रदेश की जनता ने 2017 में सरकार का गठन किया था। उस समय विधानपरिषद में समाजवादी पार्टी का बोलबाला था। वो विकास की याजनाओं में बैरियर बनने का काम करते थे। हम विकास की योजनाओं को किसी प्रकार से पास करा पाते थे लेकिन आज भाजपा बहुमत की ओर विधानपरिषद में भी अग्रसर है।

सीएम योगी ने कहा कि विधान परिषद में बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा को विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, लोककल्याण, गरीब कल्याण, पंचायत स्तर पर या



स्थानीय निकाय स्तर पर तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यवधान नहीं रहेगा। इसलिए हमको सभी सीटों पर विजय प्राप्त करनी होगी। बैठक का समापन नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधानपरिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की।

ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्यों, पार्षदों, सभासदों, महापौर, विधायक, सांसदों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री से वारणसी से ग्राम पंचायत सदस्य मोनिका पाठक ने संवाद किया। उन्होंने सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। सीएम योगी

ने उनसे पूछा ठीक ठाक काम चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि काशीवासियों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है। प्रदेश गौरवान्वित है। काशी में पिंडरा में विधायक भी भाजपा के हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही पीएम के नेतृत्व पर निश्चय बनी रहे। लखनऊ से राजाजीपुरम के पार्षद राजीव कृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके कार्यकाल में मुख्यमंत्री अन्न योजना से जनता को काफी लाभ मिला। जनता आपको धन्यवाद दे रही है। मतदान भी आपके पक्ष में किया। स्वच्छ भारत मिशन में सौचालय की व्यवस्था हमारे वार्ड में की गई। दो पिक पुलिस बूथ भी बने।

धन्यवाद देना चाहते हैं जो प्रोत्साहन मिल रहा है।

आगरा के महापौर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी से कहा कि आगरा के लोगों में हर्ष की लहर है। आम जनमानस में सरकार के प्रति अच्छे काम किये जाने की संभावनाएं आगे बन रही हैं। कानून और स्वच्छता में अमूल चूल सुधार हुए हैं। महापुरुषों को सम्मान देने की दृष्टि में काफी काम हुआ। महाराणा प्रताप और जाट समाज के योद्धा की मूर्ति तैयार की गई है। लोकार्पण आपके करकर्मलों में लोकार्पण होना है।

झांसी के पार्षद दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विकास के इतने काम हुए जिसको बखान करना मुश्किल है। एमएलसी चुनाव में हमको जीत मिलने वाली है।

1990 के बाद राज्यसभा में सौ का आंकड़ा छूने वाली पहली पार्टी बनी बीजेपी

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी 1990 के बाद राज्यसभा में सौ का आंकड़ा छूने वाली पहली पार्टी बन गई है। दरअसल राज्यसभा चुनावों में असम, त्रिपुरा और नागलैंड की एक-एक सीटों पर जीत हासिल करने के बाद इतिहास में पहली बार उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों का आंकड़ा 100 पर पहुंच गया।

हालांकि इसके बावजूद 245-सदस्यीय राज्यसभा में भाजपा अभी तक बहुमत से दूर है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया है। वर्ष 2014 में उच्च सदन में भाजपा के सदस्यों की संख्या 55 थी। उसके बाद कई राज्यों में चुनावी जीत दर्ज करने के बाद उसके आंकड़े बढ़ते रहे और अब वह सौ पर पहुंच गयी है।

इससे पहले 1990 में कांग्रेस के 108 सदस्य राज्यसभा में थे। इसके बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या लगातार घटती चली गई। एक-एक कर कई राज्यों में उसे अपनी सरकारें गंवानी पड़ीं और इसका असर राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या पर पड़ा।

हालांकि आने वाले दिनों में भाजपा की इस बढ़त पर रोक लग सकती है क्योंकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा को बढ़त मिलने के आसर हैं। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें खाली हुई हैं और इनमें से भाजपा कम से कम नौ सीटें जीत सकने की स्थिति में है।

राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 11 सदस्यों में पांच भाजपा के हैं।

प्रियंका गांधी का तंज

पीएम को परीक्षा नहीं, पेपर लीक कर करनी चाहिए चर्चा

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्वा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए।

प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कुछ परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार को उग्र में 'पेपर लीक पर चर्चा' करनी चाहिए। पिछले साल 28 नवंबर को यूपी टैटैटी पेपर लीक से लाखों युवाओं को आघात लगा था।

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, एक्शन के नाम पर दिखावटी कदमों के अलावा कुछ नहीं हुआ। यूपी के युवा आज तक नहीं जान पाए कि यूपी सरकार के किस भ्रष्ट तंत्र ने पेपर लीक को अंजाम दिया?

नतीजतन, एक और पेपर लीक। इस बार भी सरकार दिखावटी कदमों के अलावा कुछ और नहीं कर रही है। पेपर लीक की खबर लिखने वाले पत्रकार को जेल भेजा



जा रहा है। लेकिन, पेपर लीक करने वाला तंत्र सरकार में पैठ जमाए बैठा है। उस पर न कोई बुलडोजर चलता है, न कोई बदलाव आता है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड की 12 वीं कक्षा की अंग्रेजी भाषा की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बुधवार को आयोजित 24 जिलों में यह परीक्षा रद्द कर दी गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अब ये परीक्षा 13 अप्रैल को सुबह आठ बजे से आयोजित की जाएगी।

दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में देशभर के छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। छात्रों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह मेरा बहुत प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप जैसे साथियों से मिल नहीं पाया। मेरे लिए आज का कार्यक्रम विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों से इसी संवाद को लेकर प्रियंका गांधी ने पेपर लीक के मसले पर सवाल उठाए।

यूपी की चार जातियों को जनजाति में शामिल करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित



नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के चार जिलों में चार समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाला संशोधन विधेयक शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित हो गया।

आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 'संविधान (अनुसूचित जातियों) और अनुसूचित जनजातियों) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022' पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि चर्चा में 24 वरिष्ठ सदस्यों ने हिस्सा लिया और सबने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनके सुझावों को विधेयक में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने अपने राज्यों के संबंध में विचार व्यक्त किये हैं और समस्याएं रखी हैं। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि मोदी सरकार देश के हर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

उनका कहना था कि आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृतिप्रेमी होते हैं और उन्हें पेड़, पौधों और जंगल से प्रेम रहता है इसलिए हर स्थिति में उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय में किसे शामिल करना है इसको लेकर प्रस्ताव राज्य सरकारों की तरफ से आते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। किस जाति को सूची में शामिल किया जाना है

गौरतलब है कि एससी-एसटी (संशोधन) अधिनियम-2002 के

यह फैसला सरकार अकेले नहीं करती।

इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जिन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल करना है इस बारे में सारे फैसले करने का अधिकार सरकार की बजाय संसद के माध्यम से पारित करने को कहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि चुनाव के मद्देनजर सरकार यह विधेयक लेकर आई है लेकिन देश में बराबर चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों का विधेयक से कोई मतलब नहीं होता है।

सदन ने हाल ही में कर्नाटक का, अरुणाचल और त्रिपुरा से संबंधित विधेयक पारित किया और अब जल्द ही झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से जुड़े विधेयक भी पारित किये जाएंगे।

मुंडा ने कहा कि जनजाति समुदाय का विकास होना चाहिए इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। उनका कहना था कि 2013-14 से पहले का आंकड़ा देखें तो तब 119 आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों के लिए चल रहे थे और अब इनकी संख्या 367 हो गई है।

उस समय प्रति छात्र खर्च 42 हजार रुपए था जो अब प्रति छात्र एक लाख 9 हजार रुपए हो गया है। एकलव्य स्कूलों के लिए कांग्रेस के समय 12 करोड़ रुपए मिलते थे जो आज 38 करोड़ रुपए हैं।

गौरतलब है कि एससी-एसटी (संशोधन) अधिनियम-2002 के

तहत यूपी के गोंड और उसकी पर्याय जातियों धूरिया, नायक, ओझा, पठरी और राजगोंड को 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्राप्त है। ये जिले हैं- महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। शेष 62 जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति (एससी) में सूचीबद्ध किया गया है।

अलग-अलग समय पर इन 13 जिलों में से ही चार नए जिले चंदौली, संत रविदासनगर (भदोही), संतकबीरनगर और कुशीनगर बनाए गए। इन चार नवसृजित जिलों में भी गोंड और उनकी पर्याय जातियों को अनुसूचित जाति में रखा गया। इसका इन जिलों के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि मूल जिले में उन्हें एसटी का दर्जा मिलता था, जिसे नए सृजित जिले में भी बरकरार रखना चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2013 में इस मांग को जायज ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। प्रदेश सरकार के माध्यम से यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई।

पिछले साल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर रिमांडर भेजा। इसके बाद संसद में विधेयक पेश होने की प्रक्रिया शुरू हुई। किसी भी नए जिले में एसटी का दर्जा तभी मिल सकता है, जब संसद से संबंधित विधेयक पास हो।

केजरीवाल के घर हमला मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हंगामे को लेकर स्थिति रिपोर्ट पेश करे।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने मामले की जांच विशेष जांच टीम से कराने की आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि दिल्ली पुलिस सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट पेश करे।

खंडपीठ ने सीसीटीवी फुटेज में कैद घटना के वीडियो को अदालत में देखा। खंडपीठ ने कहा

कि हंगामा कर रही भीड़ अनियंत्रित थी। उन्होंने बैरियर तोड़ दिया और कुछ ने तो गेट पर भी चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की।

दिल्ली पुलिस ने इस घटना के संबंध में जारी नोटिस का कड़ा विरोध किया और खंडपीठ को बताया कि अब तक उन्होंने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच अभी जारी है।

दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि पुलिस मुख्य मंत्री के सचिव से मामले के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के लिये मिल रही है। पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय

जैन ने बताया कि घटना के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने और गिरफ्तारियां किये जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने अदालत में गुहार लगा दी। उन्होंने कहा कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित है।

मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि केजरीवाल के आवास के बाहर हंगामा करने के कारण करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया गया था। विधानसभा में कुछ दिनों पहले कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर दिये गये अरविंद केजरीवाल के बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे की अगुवाई में केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था।

सीएम योगी का आदेश : अस्पतालों में खाली पदों पर जल्द की जाएं भर्तियां

लखनऊ, 01 अप्रैल (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मानव संसाधन की कमी से जुड़ अस्पतालों में खाली पदों को जल्द भरा जाए। प्रदेश की जर्जर एम्बुलेंस की गाड़ियों को हट कर नए वाहनों को खरीद की जाए। उन्होंने आम लोगों के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तेजी से सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी ने शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने आला अधिकांशियों को उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में इलेक्ट्रिक सेप्टी, फायर सेप्टी और स्वच्छता अभियान



को प्रभावी ढंग से लागू करें। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को सभी सुविधा मुहैया कराने की भी निर्देश दिए।

प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को टीका लग चुका है। 83 प्रतिशत से अधिक पात्र वयस्क टीके की दोनो डोज ले चुके हैं। 15-17 आयु वर्ग के लगभग 93.20 प्रतिशत किशोरों ने

टीका कवर ले लिया है। 24 लाख से अधिक पात्र लोगों को प्री-कोशन डोज भी दी जा चुकी है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में से 10 लाख से ज्यादा बच्चों को टीकाकवर मिल चुका है। बीते 24 घंटों में 01 लाख 20 हजार 835 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 50 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 20 लोगों ने संक्रमण को मात दी।